हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 331 बेमेतरा, सोमवार 27 जुलाई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

समाचार सार

वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद रफ्तार पकड़ेगा देश का टू-व्हीलर निर्यात

नईदिल्ली। देश की प्रमुख टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियां चालू वित्त वर्ष में कदम रखते हुए सतर्कता के साथ तेजी की उम्मीद जता रही हैं। कंपनियों का मानना है कि दुनिया भर में बढ़ रही अनिश्चितता के माहौल के बावजूद निर्यात में आई तेजी उनके कारोबार को मजबूती देगी। देश की बड़ी टू-व्हीलर कंपनियां हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर कंपनी और बजाज ऑटो ने वित्त वर्ष 2025-26 में निर्यात के मामले में बड़े आंकड़े हासिल किए हैं।

अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ पर भारत को बड़ी राहत

नईदिल्ली। अमेरिका की तरफ से लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के मामले में भारत को व्यापार वार्ताओं के जरिए बड़ी राहत मिलती दिख रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी बयान के मुताबिक, अमेरिका के साथ हुई ट्रेड बातचीत के दम पर भारत को अतिरिक्त टैरिफ के 'लोअर टियर' (निचले स्तर) में रखा गया है, जिससे देश के मुख्य निर्यातकों को बड़ा फायदा हुआ है। मंत्रालय के मुताबिक, अमेरिका को होने वाले भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स (दवाइयां) और स्मार्टफोन शामिल हैं।

बिना प्रॉपर्टी खरीदे करें रियल एस्टेट में निवेश

नईदिल्ली। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन लाखों रुपये की जरूरत, कम लिक्विडिटी और एक ही प्रॉपर्टी में पैसा फंसने के जोखिम की वजह से अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो जल्द ही आपके लिए एक नया विकल्प आने वाला है। अब आप बिना सीधे प्रॉपर्टी खरीदे, म्युचुअल फंड के जरिए भी रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ में निवेश कर सकेंगे। इसी जरूरत को देखते हुए, एडलवाइस म्युचुअल फंड भारत का पहला आरईआईटी-ओरिएंटेड इंडेक्स फंड लॉन्च करने जा रहा है। 'एडेलवाइस निफ्टी आरईआईटी और रियल्टी इंडेक्स फ़ंड नाम का यह फंड निवेशकों को एक ही म्युचुअल फंड के जरिए लिस्टेड रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश का अवसर देगा।

इंश्योरेंस कंपनी की सभी दलीलें खारिज

नईदिल्ली। महाराष्ट्र के पालघर में मोटर एक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने साल 2017 के एक मामले में घायल को 1.06 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। 2017 में मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर हुए एक सड़क हादसे में 31 साल का एक व्यक्ति लकवाग्रस्त हो गया था। पीड़ित ऋषभ विजय कुमार चोपड़ा होटल मैनेजमेंट के पूर्व छात्र हैं।

परीक्षा सुधारों पर बड़ा एलान, नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन

नई दिल्ली (ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम 7 बजे के करीब अपने सोशल मीडिया पर परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर नया वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया कि परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य से छेड़छाड़ की, वे आज जेल में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य के लिए लगातार विभिन्न कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेल में हैं। इसके लिए पहले ही फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार संसद में ऐसे नए कानून की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, जिसमें कड़े कानूनी प्रावधान शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रणाली को

पीएम मोदी ने जारी किया नया वीडियो

भरोसेमंद, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाना जरूरी है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में हाई पावर्ड टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि यह टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर काम करेगी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

यह मामला 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा है। इस मामले के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी एक महीने से प्रदर्शन कर रही है। वहीं, सोनम वांगचुक ने 26 दिन तक अनशन किया और संसद में भी इस मुद्दे पर सांसदों ने हंगामा किया।

मन की बात में पीएम मोदी ने युवाओं का फिर बढ़ाया हौसला, कारगिल के वीरों को भी किया नमन

आज का भारत वीरों की गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाता है: पीएम मोदी

नई दिल्ली (ए)। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर मन की बात के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीद सैनिकों को नमन किया और उनके योगदान को याद किया।

पीएम मोदी ने इस दौरान युवाओं का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने खेल से लेकर तकनीक तक में युवाओं के योगदान को सराहा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें गर्व से भर देता है, यह दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची-ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।

फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी पांच छात्रों ने गोल्ड मेडल जीता और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के छात्रों ने गोल्ड या सिल्वर

मेडल जरूर जीते हैं। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी छात्रों ने गोल्ड मेडल जीते। ये अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है।

बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी छात्रों ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं, गणित ओलंपियाड में हमारे छात्रों ने दो स्वर्ण और चार रजत पदक अपने नाम किये। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस साल एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है- वन राइड, वन नेशन, वन सेल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।

भारत लगातार अपनी तकनीकी क्षमता को मजबूत कर रहा- इस दौरान, पीएम मोदी ने रक्षा उत्पादन, रक्षा निर्यात और मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ-साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौ-सेना में आईएनएस महेंद्रगिरि शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन कियागया है, भारत में ही बना है।

इसमें 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इसी महीने डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है।

हमारे युवा अन्वेषकों ने वो कर दिखाया

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। इस निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा अन्वेषकों ने वो कर दिखाया, कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की कुशलता, जुनून और धैर्य दिखाया।

पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला

पीएम मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में Japan Open का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है।

मन की बात में बार-बार छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात: मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री साय ने फाफाडीह में युवाओं और आमजनों के साथ सुनी मन की बात की 136वीं कड़ी

प्रधानमंत्री मोदी ने कैच द रेन अभियान के तहत कोरबा में जल संरक्षण के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के फाफाडीह स्थित दया भवन में युवा साथियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 136वीं कड़ी का श्रवण किया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के साथ संवाद का एक ऐसा सशक्त मंच बन गया है, जो समाज के बीच हो रहे सकारात्मक और प्रेरणादायी कार्यों को राष्ट्रीय पहचान दिलाता है।

देशभर के लोगों को प्रत्येक माह इस कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा रहती है। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं, नवाचारों और जन-अभियानों को सामने लाते हैं, जो बिना किसी प्रसिद्धि या व्यक्तिगत अपेक्षा के समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के नवाचारों को लगातार मिल रही राष्ट्रीय पहचान- मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले कुछ महीनों में मन की बात कार्यक्रम में लगातार छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों, सांस्कृतिक विरासत और नवाचारों का उल्लेख किया जाना प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले मल्हार की समृद्ध पुरातात्विक विरासत, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे अभिनव आयोजनों का उल्लेख कर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक शक्ति, जनजातीय परंपराओं और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया था। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा कोरबा में जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण की दिशा में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों का उल्लेख किया गया। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश की उपलब्धियों का राष्ट्रीय मंच पर उल्लेख किए जाने से न केवल छत्तीसगढ़वासियों का उत्साह बढ़ता है, बल्कि राज्य के नवाचारों और जनभागीदारी आधारित विकास मॉडल को देशभर में नई पहचान भी मिलती है।

12वीं हिंदी पेपर लीक पर छात्रों का प्रदर्शन शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग तेज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड के हिंदी विषय का पेपर लीक होने के मामले को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आज रविवार को राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी उठाई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों से प्रतियोगी और बोर्ड परीक्षाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।

प्रदर्शन को एनएसयूआई का भी समर्थन मिला। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता छात्रों के साथ धरने में शामिल हुए और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग दोहराई।

छात्रों ने री-नीट परीक्षा से जुड़े घटनाक्रम के बाद आत्महत्या करने वाली हरिका राव के परिवार को न्याय और उचित मुआवजा देने की भी मांग की।

सीजीपीएससी घोटाला: सीबीआई के बाद ईडी की एंट्री

करप्शन मामले में भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति: साय

रायपुर। सीजीपीएससी घोटाला मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो चुकी है. टामन सिंह सोनवानी से रिमांड अवधि के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से पूछताछ की जाएगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भाजपा सरकार को करप्शन मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने वाला बताया.

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार में प्रदेश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था. प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से सीजीपीएससी घोटाले की जांच का वादा किया था. हमारी (भाजपा) पार्टी

करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है. उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी अपराध करेगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी. जो भी दोषी पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है.

मन की बात में छत्तीसगढ़ का जिक्र- प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड में आज छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री छग का जिक्र करते हैं. बीते दिनों बस्तर पण्डुम, मल्हार का ताम्र पत्र का जिक्र मन की बात हुई थी. पीएम मोदी ने इस एपिसोड में कैच द रैन अभियान में अपनी अलग पहचान बनाने वाले कोरबा का जिक्र किया. प्रधानमंत्री ने गणेश चतुर्थी में अपने गांव से बनी से बनी मिट्टी की मूर्ति घर लाने का आव्हान किया.

बीजेपी के लिए देश सर्वोपरि है: साय - केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर रविवार को सीएम साय ने कहा कि बीजेपी के लिए देश सर्वपरि है. धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है. वह संगठन के प्रभारी भी रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी सिद्धांतवादी पार्टी है. हम जनता की सेवा और देश की सेवा के लिए सरकार में आते हैं. धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश के संगठन के प्रभारी भी रहे हैं।

शिवकाशी में अवैध पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट, तीन की मौत, कई घायल

शिवकाशी। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास रविवार को एक अवैध पटाखा गोदाम में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। विस्फोट के बाद लगी भीषण आग और लगातार हुए धमाकों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वैध गोदाम में

धमाका-यह हादसा शिवकाशी तालुक के सेंगामलपट्टी गांव में हुआ, जहां एक अवैध गोदाम और निर्माण इकाई में कथित तौर पर पटाखे बनाने का काम चल रहा था। तेज धमाके से इमारत को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि लगातार हो रहे पटाखों के विस्फोट से आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया।

जनता को न भटकाएं समय पर करें काम

आयकर विभाग को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दो टूक

मुंबई (ए)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि उनका काम सिर्फ कर वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों को समय पर और बिना परेशानी के सेवाएं देना भी उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को छोटे-छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। अधिकारियों को नियमों का पालन करते हुए लोगों के वैध दावों और अधिकारों का समय पर निपटारा करना चाहिए। रविवार को मुंबई के नरीमन पॉइंट में आयकर विभाग की नई 13 मंजिला इमारत आयकर सिंधु के उद्घाटन के दौरान वित्त मंत्री ने अधिकारियों को प्रशासनिक जवाबदेही, ईमानदारी और संवेदनशीलता का संदेश दिया। करीब 1.13 लाख वर्ग फीट में बनी इस इमारत के उद्घाटन समारोह में उन्होंने विभाग की कार्यशैली पर भी खुलकर बात की।

अधिकारियों को भी समझना चाहिए आम आदमी की परेशानी-वित्त मंत्री ने कहा कि इस भवन के निर्माण के लिए जरूरी मंजूरियां हासिल करने में खुद आयकर विभाग के अधिकारियों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब एक शक्तिशाली सरकारी विभाग के अधिकारियों को विभिन्न मंजूरियों के लिए भटकना पड़ता है, तो आम नागरिकों की परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस अनुभव से अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और अनावश्यक देरी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारियों के पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। इसलिए उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए।

1973 से खाली पड़ी जमीन पर हुए कब्जों पर जताई नाराजगी

निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस जमीन पर आज नई इमारत खड़ी है, वह 1973 से आयकर विभाग के पास थी। लंबे समय तक उसका उपयोग नहीं होने के कारण वहां अवैध कब्जे हो गए। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण बताते हुए कहा कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करना विभाग की जिम्मेदारी है।

सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोलिंग स्टॉक और मेंटेनेंस सिस्टम को आधुनिक बनाया गया

अब जनरल-स्लीपर कोच में नहीं होगी सीट की मारामारी

नई दिल्ली (ए)। सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोलिंग स्टॉक और मेंटेनेंस सिस्टम को आधुनिक बनाया गया है। 2014-26 के दौरान एलएचबी कोचों का उत्पादन बढ़कर 49,366 हो गया है। रेलवे का स्वदेशी सुरक्षा सिस्टम कवच 4.0 दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा जैसे व्यस्त रेल मार्गों के 2,490 रूट किलोमीटर पर सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे जनरल और स्लीपर श्रेणी के यात्रियों पर फोकस बढ़ा रहा है।

रेलवे ने संसद में बताया, लंबी दूरी की ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही कम और मध्यम आय वर्ग के यात्रियों के लिए 17 हजार नए नॉन एसी कोच तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही अमृत भारत ट्रेनों का भी विस्तार किया जा रहा है। रेलवे के मुताबिक, साल भर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या एक जैसी नहीं रहती है। छुट्टियों और त्योहारी सीजन में लोकप्रिय रूटों पर ट्रेनों में पूरी क्षमता तक भीड़ रहती है।

इसे देखते हुए पिछले दो वर्षों में लंबी दूरी की कई ट्रेनों में स्थायी रूप से अतिरिक्त जनरल कोच जोड़े गए हैं। वर्ष 2024-25 में 1,250 जनरल कोच विभिन्न लंबी दूरी की ट्रेनों में लगाए गए, ताकि हर ट्रेन में कम से कम चार जनरल कोच उपलब्ध हों। वर्ष 2025-26 में 870 अतिरिक्त कोच ट्रेनों में लगाए गए है। इनमें 160 जनरल कोच शामिल हैं। वहीं 2026-27 में 30 जून तक 190 और कोच बढ़ाए गए हैं, जिनमें 20 जनरल कोच हैं। रेलवे का कहना है कि इन प्रयासों का उद्देश्य आम यात्रियों को बेहतर

सुविधा और अधिक सीट उपलब्ध कराना है। रेलवे के करीब 89 हजार कोचों में करीब 70 फीसदी नॉन एसी और 30 फीसदी एसी कोच है।

मौजूदा नीति के तहत 22 कोच वाली मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में 12 जनरल-नॉन एसी स्लीपर कोच और 8 एसी कोच रखे जा रहे है। ताकि ज्यादा यात्रियों को सस्ती यात्रा का विकल्प मिल सके। इसके अलावा अनारक्षित यात्रियों के लिए पैसेंजर, मेमू और ईएमयू सेवाएं भी चलाई जा रही है। रेलवे के अनुसार, निम्न-मध्यम आय वर्ग के यात्रियों के लिए शुरू की गई अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह नॉन एसी है। इसकी मौजूदा रेक में 11 जनरल, 8 स्लीपर, एक पैंट्री कार और दो लगेज सह दिव्यांग कोच है। इन ट्रेनों में वदे भारत स्लीपर की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई है। रेलवे ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के साथ ऑनलाइन टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े पर भी सख्ती बढ़ाई है। रेल वन ऐप को अब तक 4.55 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड किया जा चुका है। ऐप के जरिए रोजाना औसतन 9.65 लाख टिकट बुक किए जा रहे हैं। जून 2025 से जून 2026 के बीच रेलवे में कुल 65.08 करोड़ आरक्षित टिकट बुक हुए।

कवच सिस्टम का हो रहा विस्तार

रेलवे ने जानकारी दी, सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोलिंग स्टॉक और मेंटेनेंस सिस्टम को आधुनिक बनाया गया है। 2014-26 के दौरान एलएचबी कोचों का उत्पादन बढ़कर 49,366 हो गया है। रेलवे का स्वदेशी सुरक्षा सिस्टम कवच 4.0 दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा जैसे व्यस्त रेल मार्गों के 2,490 रूट किलोमीटर पर सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। कवच सिस्टम का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। इसे 21,937 रूट किलोमीटर पर लगाने का काम जारी है। इसके अलावा 7,435 लोकोमोटिव और 1,200 ईएमयू/एमईएमयू ट्रेनों में भी कवच लगाने की प्रक्रिया चल रही है। रेलवे के अनुसार, 2014 से जून 2026 तक 5.56 लाख से अधिक भर्तियां पूरी की जा चुकी हैं। खाली पदों को भरने के लिए वार्षिक भर्ती कैलेंडर के तहत प्रक्रिया जारी है।

जलावर्धन योजना में घटिया निर्माण की खुली पोल! तीन माह से पहले ही उखड़ी सड़क, जिम्मेदार कौन

बरमकेला/मूक पत्रिका

बरमकेला नगर में जलावर्धन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को खोदा गया था। पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य संबंधित ठेकेदार द्वारा कराया गया, जिसकी निगरानी की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई विभाग) की थी। लेकिन कार्य पूरा होने के तीन माह भी पूरे नहीं हुए हैं और सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह उखड़ गई है, बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं और बरसात के कारण उनमें पानी भर गया है। इससे विभाग और ठेकेदार दोनों की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है।

सरकारी योजनाओं में जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। लेकिन जब निर्माण कार्य अपनी निर्धारित उम्र तो दूर, तीन माह भी पूरा नहीं कर पाता, तब निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि सड़क मरम्मत कार्य कुछ ही समय में अपनी वास्तविकता बयां करने लगा?

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। जहां-जहां पाइपलाइन बिछाई गई थी, वहां सड़क की मरम्मत जल्दबाजी में की गई। आज स्थिति यह है कि सड़क की ऊपरी परत उखड़कर बाहर आ चुकी है और कई स्थानों पर सड़क धंस गई है। बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है।

तीन माह भी नहीं टिक सका निर्माण कार्य

आमतौर पर किसी भी सड़क निर्माण या मरम्मत कार्य से वर्षों तक टिकाऊ होने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन यहां स्थिति इसके ठीक विपरीत दिखाई दे रही है। निर्माण कार्य को अभी तीन माह भी पूरे नहीं हुए हैं और सड़क की गुणवत्ता की पोल खुल चुकी है। यह न केवल निर्माण एजेंसी बल्कि कार्य की निगरानी करने वाले विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

यदि सड़क मरम्मत कार्य निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप किया गया था, तो इतनी कम अवधि में उसका उखड़ जाना समझ से परे है। क्या निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया? क्या निर्माण कार्य के दौरान आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण किया गया था? यदि किया गया था, तो उसकी रिपोर्ट क्या कहती है?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की निगरानी पर सवाल

जलावर्धन योजना के कार्यों की देखरेख की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की होती है। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि निर्माण कार्य के दौरान विभागीय अधिकारियों ने कितनी बार निरीक्षण किया? क्या कार्य पूर्ण होने के बाद गुणवत्ता की जांच की गई थी? यदि सड़क निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं था, तो कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई विभाग की जिम्मेदारी केवल पाइपलाइन बिछाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि सड़क को पूर्व स्थिति में गुणवत्तापूर्ण तरीके से बहाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि सड़क निर्माण कार्य तीन माह भी नहीं टिक पाया है, तो विभागीय निगरानी पर सवाल उठना लाजिमी है।

ठेकेदार की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में

सड़क निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संबंधित ठेकेदार की कार्यशैली भी कटघरे में खड़ी दिखाई दे रही है। यदि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया गया है, तो यह सीधे तौर पर सरकारी धन और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ माना जाएगा।किसी भी ठेकेदार को कार्य आवंटित करने का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराना होता है, लेकिन जब कार्य तीन माह भी नहीं टिके, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या निर्माण कार्य केवल कागजों में गुणवत्तापूर्ण था? क्या मौके पर वास्तव में मानकों का पालन किया गया बरमकेला नगर की इन सड़कों से प्रतिदिन सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं। दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह सड़क किसी खतरे से कम नहीं है। बरसात के कारण गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग, व्यापारी और आम नागरिक सभी इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं।

यदि समय रहते सड़कों का गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण नहीं कराया गया, तो आने वाले दिनों में यह समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। ऐसे में यदि किसी दुर्घटना में किसी नागरिक की जान-माल का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?

जांच और कार्रवाई की मांग

नगरवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जलावर्धन योजना के अंतर्गत कराए गए सड़क मरम्मत कार्य की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए। निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाए तथा यदि अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।

÷लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जलावर्धन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के बाद किए गए सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य की गुणवत्ता अत्यंत निम्न स्तर की है। कई स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसे देखते हुए नगर पंचायत बरमकेला द्वारा संबंधित विभाग को पत्र लिखकर क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने के लिए कहा गया है, ताकि आम नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।÷

दीपक विश्वकर्मा

मुख्य कार्यपालन अधिकारी बरमकेला

÷कुछ स्थानों पर बारिश के कारण पानी जमा हो जाने तथा कुछ जगहों पर वाहनों की अधिक आवाजाही होने के कारण सड़क की कॉम्पेक्शन प्रक्रिया अच्छी तरह नहीं हो पाई होगी। इसी वजह से सड़क की यह स्थिति निर्मित हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मैं कल इसकी जांच करवाता हूं

भीम लाल खरे

एसडीओ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसाः माधोपाली पुल पर तेज बहाव में कार बही, चालक की तलाश जारी..

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एक बड़ा हादसा सामने आया है। माधोपाली पुल पार करते समय तेज बहाव में एक कार बह गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार में घोटला बड़े निवासी देवनारायण पटेल सवार थे।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। समाचार लिखे जाने तक अमझर पुल के आसपास रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। पुलिस, प्रशासन और स्थानीय ग्रामीण संयुक्त रूप से लापता देवनारायण पटेल की तलाश में जुटे हुए हैं।हादसे के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू टीम के साथ सहयोग करते हुए लापता व्यक्ति के सकुशल मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं।फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कार किस परिस्थिति में पुल पर पहुंची और तेज बहाव में कैसे बह गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान उफनते नालों, पुल-पुलियों और जलभराव वाले मार्गों को पार करने से बचें तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। समाचार लिखे जाने तक देवनारायण पटेल का कोई सुराग नहीं मिल सका था। पुलिस और प्रशासन का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है तथा मामले की जांच भी की जा रही है।

माय भारत पोर्टल में पंजीयन और देश सेवा करने कलेक्टर एसपी ने युवाओं को किया प्रोत्साहित..

सारंगढ़ बिलाईगढ/मूक पत्रिका

खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा सारंगढ़ के सीपीएम कॉलेज में कारगिल विजय दिवस पर 'माय भारत' कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के छात्र छात्राओं की उपस्थिति में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू एवं पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा शामिल हुए। अतिथियों ने युवाओ को देश सेवा के लिए प्रोत्साहित किया और माय भारत पोर्टल में पंजीयन करने की अपील की। इस अवसर पर प्रभारी खेल अधिकारी सह डिप्टी कलेक्टर शिक्षा शर्मा, कालेज के प्राचार्य आदि उपस्थित थे। माय भारत, यह एक फिजीकल इकोसिस्टम (भौतिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का मिश्रण) के माध्यम से युवा सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही अनुभवात्मक शिक्षण के अवसर, स्वयंसेवा के अवसर और मेगा इवेंट्स में भाग लेने जैसे सार्थक अवसर प्रदान करता है , इसके अलावा माय भारत प्रोफाइल, सीवी बिल्डर और मेंटरशिप जैसे मूल्यवान संसाधन भी उपलब्ध कराता है। माय भारत पोर्टल लिंक https://mybharat.gov.in/ है। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामले विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय, माय भारत की स्थापना युवा विकास, सहभागिता और राष्ट्र निर्माण के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य नेतृत्व, स्वयंसेवा, अनुभवात्मक शिक्षा, नवाचार और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देकर युवाओं को सशक्त बनाना है, साथ ही ÷सेवा भाव÷ और ÷कर्तव्य बोध÷ के मूल्यों को पोषित करना है । साझेदारी और युवा-केंद्रित पहलों के माध्यम से, एमवाई भारत युवाओं को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाता है ।

बेमेतरा में जीएसटी अधिकारियों और व्यापारियों की महत्वपूर्ण बैठक आज

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले के समस्त व्यापारियों के लिए सोमवार, 27 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में राज्य कर अपर आयुक्त (मुख्यालय, नवा रायपुर) टी.आर. ध्रुवे एवं संयुक्त कर आयुक्त, राज्य कर दुर्ग संभाग श्रीमती गुलापा पुरसेठ विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बैठक के दौरान जीएसटी से जुड़े विभिन्न विषयों, व्यापारियों की समस्याओं, कर संबंधी प्रक्रियाओं तथा विभागीय समन्वय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। यह बैठक अपराह्न 3:00 बजे नए जीएसटी कार्यालय (कसार पेट्रोल पंप के आगे, स्टेडियम के बाजू में, दुर्ग रोड, कंतेली, बेमेतरा) में आयोजित होगी।

सहायक आयुक्त राज्य कर, बेमेतरा सुरेंद्र पटेल एवं जीएसटी कार्यालय परिवार बेमेतरा ने जिले के सभी व्यापारी भाइयों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण बैठक में समय पर उपस्थित होकर चर्चा का लाभ उठाएं और विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें।

31 जुलाई तक होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा पंजीयन

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ 2026 में ऋणी एवं अऋणी कृषकों का फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है। किसान 31 जूलाई 2026 तक बैंक, सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के माध्यम से अपने अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे - बाधित रोपाई, रोपण जोखिम- अधिसूचित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण अधिसूचित मुख्य फसल की बोआई, रोपण, अंकुरण नहीं हो पाने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा, साथ ही ओलावृष्टि, जलभराव, बादल का फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम होने वाली बरसात से फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिले के ऋणी एवं अऋणी कृषक बीमा का लाभ लेने हेतु जिला के सहकारी बैकों में तथा सेवा सेतु केन्द्रों के माध्यम से आवेदन कर फसल बीमा करा सकते है। उप संचालक कृषि जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष खरीफसीजन के धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, मूंगफली,उड़द एवं मूंग फसल शामिल है, जिसके लिये खरीफ फसल हेतु कुल बीमित राशि ऋणमान के आधार पर 2 प्रतिशत ही प्रीमियम राशि किसानों द्वारा देना होगा। इस वर्ष भी बजाज जनरल इन्सुरेंस कंपनी लिमिटेड अधिकृत बीमा कंपनी होगी। उप संचालक कृषि द्वारा जिले के सभी किसानों से आग्रह किया है कि अधिक से अधिक किसान अपने फसलों का फसल बीमा अनिवार्य रूप से करावे, ताकि प्राकृतिक जोखिमों से होने वाली आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने सभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों एवं मैदानी अमलो को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए सभी ऋणी एवं अऋणी किसानो को बीमा आवरण में लाने हेतु निर्देशित किया है।

सारंगढ़ पुलिस की कार्रवाईः 30 लीटर महुआ शराब के साथ महिला गिरफ्तार, रेड़ा गांव में दी गई दबिश..

सारंगढ़-बिलाईगढ/मूक पत्रिका

जिले में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सारंगढ़ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्राम रेड़ा में छापेमारी कर अवैध महुआ शराब की बिक्री कर रही एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 30 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है।पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमीषा पाण्डेय के मार्गदर्शन में अवैध शराब, जुआ और सट्टे के खिलाफविशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 25 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रेड़ा के बजरंग बली चौक के पास एक मकान में बिक्री के लिए बड़ी मात्रा में महुआ शराब रखी गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रमोद यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान सुशीला सारथी, पति राजकुमार, निवासी ग्राम रेड़ा के कब्जे से सफेद प्लास्टिक की पन्नी में रखी 30 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 6,000 रुपये बताई गई है।पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी महिला के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रमोद यादव, सउनि अंजान सिंह, पीएसआई चंचल, महिला आरक्षक भुवनेश्री साहू तथा सिटी कोतवाली सारंगढ़ के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने कहा है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

जिला साहू संघ के गठन के बाद कई रचनात्मक कार्यों पर बनी सहमति

बेमेतरा/मूक पत्रिका

ग्राम पंचायत भवन बरगा मैं पंजीकृत संख्या 122202651838 जिला साहू संघ की बैठक रखी गई , जिसमें जिला एवं तहसील के पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। जिला साहू संघ के संयोजक शत्रुघ्न सिंह साहू ने कहा कि संघ का उद्देश्य पारदर्शी सशक्त एवं शुद्ध समाज का गठन कर रचनात्मक कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समाज को आगे बढ़ाना है। रचनात्मक कार्यों में मुख्यतः विधवा विस्थापन, गरीब -निर्धन कन्या विवाह, प्रतिभावान बच्चों के पढ़ाई के लिए आगे योजना बनाना एवं सम्मान करना, बुजुर्ग महिला - पुरुषों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए कार्य योजना बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिष्ठित सामाजिक बंधुवो को न्याय दिलाना, जल , वृक्षारोपण एवं गौ संरक्षण के लिए जागरुकता एवं संरक्षण पर विशेष कार्य करने और सामाजिक न्याय मैं सुगमता लाने का संकल्प लिया गया। जिला साहू संघ के सुरेश कुमार साहू बरगा की अध्यक्षता में गठित संगठन मै, जिला महासचिव गंगा राम साहू, उपाध्यक्ष टेक राम साहू रौद्रा, तखत राम साहू बरगा, जिला महासचिव गंगा राम लालपुर , कोषाध्यक्ष मोहन राम साहू हरदास , जिला सलाहकार - अंत राम साहू बरगा, श्यामलाल भेड़नी, गुहाराम साहू भेडरावनी, संगठन सचिव मुकेश कुमार? बेमेतरा, महिला प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्रीमती सुषमा साहू कृष्ण -- बिहार बेमेतरा एवं जिला उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता साहू बेमेतरा को बनाया गया है, वही न्याय प्रकोष्ठ जिला संयोजक आनंद प्रकाश साहू, अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ संयोजक अशोक साहू सोन चिरैया, युवा प्रकोष्ठ संयोजक नंदकुमार जेवरा एन अंधियार खोर, किसान प्रकोष्ठ युवराज साहू पिपरिया साजा किसान प्रकोष्ठ महासचिव लक्षी राम साहू, सहसंयोजक गिरधर साहू श्यामपुर कांपा युवा प्रकोष्ठ महासचिव गंगाधर साहू श्यामपुर कांपा, युवा प्रकोष्ठ सह संयोजक नेतराम साहू सोन चिरैया, न्याय प्रकोष्ठ सहसंयोजक धनीराम साहू सेमरिया को बनाया गया है।

तहसील साहू संघ अध्यक्ष साजा उमाशंकर साहू डूंगी तराई उपाध्यक्ष करण साहू घोटवानी बलदाऊ साहू परस बोर्ड को बनाया गया है बेमेतरा तहसील साहू संघ अध्यक्ष प्रमोद कुमार साहू किरतपुर सचिव खेमराज साहू सेमरिया को बनाया गया है यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार साहू द्वारा दी गई है।

प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने 'हर घर तिरंगा' अभियान का शुभारंभ किया, 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत पौधारोपण; 120 युवाओं ने ली भाजपा की सदस्यता

दरभा के जैगूर में सामूहिक रूप से सुनी गई 'मन की बात', वनाधिकार पत्रों का वितरण

बीजापुर/मूक पत्रिका

बिते रविवार को भैरमगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत दरभा के जैगूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 136वें संस्करण का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुना।

दरभा में बदलाव का जिक्र-कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि दरभा कभी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, जहां पहुंचना भी कठिन था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में किए गए प्रयासों से क्षेत्र में शांति और विकास का वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता इस सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है।

प्रधानमंत्री ने दिया जनभागीदारी का संदेश-'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को नमन किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, जनभागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान, युवाओं के नवाचार और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका पर विस्तार से अपने विचार रखे। साथ ही छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जल संरक्षण के कार्यों की सराहना भी की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री के संदेशों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

छह हितग्राहियों को मिले वनाधिकार पत्र-कार्यक्रम के बाद प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने छह पात्र हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा और उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार वनाधिकार पत्र केवल भूमि का अधिकार नहीं, बल्कि आदिवासी परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने हितग्राहियों से भूमि का सदुपयोग कर कृषि और आजीविका को सशक्त बनाने का आह्वान किया।

'हर घर तिरंगा' की शुरुआत, विद्यार्थियों का सम्मान-मंत्री ने नीट-2026 में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। साथ ही 'हर घर तिरंगा' अभियान का शुभारंभ करते हुए ग्रामीणों को तिरंगा भेंट किया। इसके बाद 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने की अपील की।

120 युवाओं ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता-कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के 120 युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने नवसदस्यों का पुष्पमाला और भाजपा गमछा पहनाकर स्वागत किया तथा उन्हें संगठन और जनसेवा में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद-कार्यक्रम में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष जी. वेंकट, प्रदेश प्रवक्ता टिकेश्वर जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, जिला पंचायत सदस्य मैथियस कुजूर सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं कलेक्टर विश्वदीप, डीएफओ डॉ. जाधव सागर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमन कुमार झा, वन विभाग, पुलिस विभाग तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजन राष्ट्रभक्ति, जनभागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत के संकल्प के साथ संपन्न हुआ।

आज भी विकास के कोसो दूर.....?, क्रोंधा गांव में शिक्षा पर भारी बारिश उफनते नाले को पार कर स्कूल पहुंचने को मजबूर 50 बच्चे

रायगढ़/मूक पत्रिका

सरकार शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताती है और सुरक्षित व सुगम शिक्षा व्यवस्था के दावे किए जाते हैं। लेकिन जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत क्रोंधा की तस्वीर इन दावों की हकीकत बयां करती है। यहां करीब 50 छात्र-छात्राएं हर बारिश के मौसम में जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर स्कूल पहुंचने के लिए मजबूर हैं। घुटनों तक बहते पानी के बीच बच्चों का यह सफर केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं, बल्कि हर दिन जिंदगी और खतरे के बीच संघर्ष जैसा बन गया है।गौरतलब हो कि बारिश शुरू होते ही गांव को स्कूल से जोड़ने वाला नाला उफान पर आ जाता है। ऐसे में छात्र-छात्राएं साइकिल नाले के एक किनारे छोड़कर पैदल पानी के बीच से गुजरते हैं। तेज बहाव और फिसलन के कारण हर कदम पर हादसे की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद शिक्षा के प्रति बच्चों की लगन उन्हें रोज इस जोखिम को उठाने के लिए मजबूर करती है।सबसे अधिक परेशानी छात्राओं को होती है। कई छात्राएं स्कूल ड्रेस भीगने और खराब होने से बचाने के लिए अलग कपड़े साथ लेकर चलती हैं। नाला पार करने के बाद वे स्कूल पहुंचकर ड्रेस बदलती हैं और फिर कक्षाओं में शामिल होती हैं। लेकिन जब बारिश अधिक होने से पानी का स्तर बढ़ जाता है, तब कई दिनों तक स्कूल जाना संभव नहीं हो पाता। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई और उपस्थिति पर पड़ता है।ग्रामीणों का कहना है कि इस नाले पर पुल निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही है। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष समस्या रखी गई तथा आश्वासन भी मिले, लेकिन आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। मजबूरी में बच्चों के सामने करीब 15 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्ग से जाने का विकल्प बचता है, जो प्रतिदिन तय करना संभव नहीं है। ऐसे में अधिकांश बच्चे या तो जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हैं या फिर स्कूल से अनुपस्थित रहने को विवश हो जाते हैं। यह समस्या हर मानसून में सामने आती है, लेकिन समाधान के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। यदि समय रहते पुल का निर्माण नहीं कराया गया तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता।

जान जोखिम में डालकर शिक्षा के लिए समर्पण

क्रोंधा के बच्चों का शिक्षा के प्रति समर्पण निश्चित रूप से प्रेरणादायी है, लेकिन किसी भी संवेदनशील व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को उफनते नाले से गुजरने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या प्रशासन किसी संभावित दुर्घटना का इंतजार करेगा, या फिर समय रहते इन बच्चों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराएगा।वही ग्रामीणों का सवाल है कि जब तक पुल का निर्माण नहीं होता, तब तक इन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाएगा।इस संबंध में सेतु विभाग के कार्यपालन अभियंता संतोष भगत का कहना है कि पुल निर्माण का प्रस्ताव और विभागीय प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

स्मार्ट मीटर हटाओ, जनता को राहत दिलाओ अभियान 27 जुलाई से शुरू

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/ कांकेर बढ़ते बिजली बिलों एवं स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, कांकेर द्वारा सोमवार, 27 जुलाई 2026 से शहर कांकेर में ÷स्मार्ट मीटर हटाओ÷ अभियान की शुरुआत की जाएगी।इस अभियान की रूपरेखा एवं आगामी रणनीति को लेकर आज राजीव भवन, कांग्रेस कार्यालय, कांकेर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान को सफल बनाने एवं शहर के प्रत्येक वार्ड तक पहुंचकर आम नागरिकों को जोड़ने का निर्णय लिया गया।अभियान के तहत शहर के विभिन्न वार्डों में आम नागरिकों से संपर्क कर स्मार्ट मीटर बदलने के लिए आवेदन पत्र (फॉर्म) वितरित किए जाएंगे। भरे हुए आवेदन पत्र एकत्रित कर सामूहिक रूप से बिजली विभाग को सौंपे जाएंगे, ताकि उपभोक्ताओं की मांग पर शीघ्र कार्रवाई हो सके। इस संबंध में शहर कांग्रेस कमेटी कांकेर के अध्यक्ष यासीन करानी ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से अनेक उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता, मध्यम वर्ग एवं गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। कांग्रेस पार्टी जनता की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए उनके साथ मजबूती से खड़ी है। करानी ने कहा कि शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उद्देश्य जनता की आवाज़ को शासन एवं बिजली विभाग तक पहुंचाना है। यदि स्मार्ट मीटर बदलने एवं बढ़े हुए बिजली बिलों की समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करेगी। इसके अंतर्गत पहले बिजली विभाग को ज्ञापन एवं आवेदन सौंपे जाएंगे। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर बिजली विभाग के खिलाफ धरना-प्रदर्शन एवं पुतला दहन कर जनआंदोलन को और तेज किया जाएगा।जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री उदय प्रकाश शर्मा 'बंटी' ने शहरवासियों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान से जुड़ें, आवेदन पत्र भरें और अपने अधिकारों की लड़ाई में कांग्रेस का साथ दें, ताकि जनता को बढ़ते बिजली बिलों से राहत मिल सके। आज के इस कार्यक्रम मै ब्लॉक अध्यक्ष यासीन करानी जिला महामंत्री उदय प्रकाश शर्मा बंटी, मनोज जैन, अजय भास्वानी, मुकेश तिवारी, बबलू देवांगन, आलोक श्रीवास्तव, मुन्ना इसहाक अहमद, शेष गजबिय, सुमित राय, संत मांडवी, सूरज सोनकर, पंचराम सलाम, रंजन गौस्वामी, अशोक उइके, राहुल नाग अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे

खेत में खाद डालने गए किसान की बाइक सड़क से चोरी, पुलिस जांच में जुटी

बस्तर/मूक पत्रिका

थाना भानपुरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मधोता 02 खैरगुड़ा में शुक्रवार दोपहर एक किसान की बाइक सड़क किनारे से चोरी हो गई। घटना के समय बाइक मालिक अपने खेत में खाद डालने के कार्य में व्यस्त था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बाइक की तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खैरगुड़ा निवासी खेमेश्वर ठाकुर शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 3-4 बजे प्रतिदिन की तरह अपने खेत में खाद डालने गए थे। इस दौरान उन्होंने अपनी हिरो स्पैलेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक छ्त्र 17 चङ्ख 6420 को सड़क किनारे खड़ी कर दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसी बीच दूसरी बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात युवकों ने मौके का लाभ उठाया और खड़ी बाइक को लेकर फरार हो गए। जब कुछ देर बाद खेमेश्वर ठाकुर ने आकर देखा तो बाइक वहां नहीं थी। इसके बाद उन्होंने आसपास पता किया लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों युवक दूसरी बाइक पर आए थे। उनमें से एक युवक ने काले रंग की शर्ट पहन रखी थी। उसका कद सामान्य और शरीर दुबला-पतला है। चोरी गई बाइक सिल्वर और ब्लैक रंग की है तथा एकदम साफ-सुथरी स्थिति में थी।घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने तत्काल थाना भानपुरी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। साथ ही आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पीड़ित परिवार थबिर सिंह ठाकुर और खेमेश्वर ठाकुर ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को भी यह बाइक कहीं दिखाई दे या किसी के द्वारा बेची जा रही हो तो इसकी सूचना तुरंत थाना भानपुरी या मोबाइल नंबर 62681 37377, 95893 04307 पर दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। ग्रामवासियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए बाहरी वाहनों की संघन जांच की जाए और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

समरसता और तिरंगा अभियान को जनआंदोलन बनाने पर भाजपा का जोर

कार्यशाला में संगठनात्मक रणनीति तय, यशवंत जैन ने कार्यकर्ताओं को दिए मूलमंत्र

बीजापुर/मूक पत्रिका

भाजपा जिला कार्यालय अटल सदन में रविवार को श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान और हर घर तिरंगा-तिरंगा यात्रा को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में दोनों अभियानों को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के लिए संगठनात्मक रणनीति बनाई गई तथा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय की गई।भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान समाज में समानता, सामाजिक समरसता और सद्भाव को मजबूत करने का माध्यम है। वहीं हर घर तिरंगा अभियान प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए दोनों अभियानों को जनआंदोलन का रूप देने का आह्वान किया।

दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी ने कहा कि समरसता संकल्प अभियान सामाजिक एकता को मजबूत करेगा, जबकि हर घर तिरंगा अभियान नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और सशक्त बनाएगा। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से अपने घर पर तिरंगा फहराने, केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने तथा जनसमस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहने का आग्रह किया। अटामी ने गुरु पूर्णिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पर्व गुरु, माता-पिता और बड़ों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। गुरु के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समाज में संस्कार, समरसता और राष्ट्रसेवा की भावना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कार्यशाला में अभियान की रूपरेखा, आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों और विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियों के निर्धारण पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम के समापन पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया गया। कार्यशाला में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जी. वेंकट, प्रदेश प्रवक्ता टिकेश्वर जैन, जिला प्रभारी दीपेश अरोरा, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्रीनिवास मुदलियार, भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, जिला उपाध्यक्ष सतेंद्र ठाकुर और दयाशंकर पटेल, महामंत्री संजय लुक्कड़ एवं फूलचंद गागड़ा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पेरे पुलैया, जिला पंचायत सदस्य शंकरैया माड़वी, मैथ्यूज कुजूर, सामंतीन कोरसा, प्रीति अर्की, नगर पालिका अध्यक्ष गीता सोम पुजारी, उपाध्यक्ष भुवन सिंह चौहान, मीडिया प्रभारी प्रताप यादव, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हरिहर सहनी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष जागर लक्ष्मैया, जिला मंत्री हरीश निषाद एवं बलदेव उरसा, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सुखमन कश्यप, महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य माया झाड़ी, जया देवी, जनपद अध्यक्ष पूर्णिमा तेलम, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष संदीप तेलम, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष हितेंद्र नाग, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उर्मिला तोकल, मंडल अध्यक्ष अशोक राव, तीरथ जुमार, नरसिंह रेड्डी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मीटिंग में सजल मधु नें कहा बैठक से पहले मिला धमकी हुआ गाली-गलौच ,एक ग्रामीण नें कहा मुआब्जा के लिए ना बनाएं मुर्गा फार्म, secl का ग्रामीणों नें जमकर किया विरोधज्मीटिंग के बाद जमकर हंगामा..

धरमजयगढ़/ रायगढ़ /मूक पत्रिका

धरमजयगढ़ क्षेत्र के दुर्गापुर, शाहपुर समेत कई प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने स्श्वष्टरु की प्रस्तावित कोयला खदान परियोजना के विरोध में बड़ी बैठक शाहपुर के मैदान में आयोजित किया गया।

इस बैठक में सजल मधु में मंच से कहा की स्द्गष्य का विरोध करने पर उनको धमकी मिल रहा हैं और उनके साथ मीटिंग से पहले गाली गलौच हुआ, वही एक ग्रामीण नें मंच से कहा की कंपनी के त्र.रू नें कहा हैं कि कई लोंग आकर आग्रह कर रहें जल्दी अधिग्रहण करें अन्यथा उसका फार्म गिर जाएगा। वही भरी सभा में ग्रामीण नें कहा की मुआब्जा के लिए ना फार्म ना बनाएं साथ ही बैठक में मुख्य रूप से बिना समर्थन उड़ाया गया ड्रोन और थाने में हुई शिकायत को लेकर खूब चर्चा हुई, कहा गया की अम्बेटिकरा के बैठक में ज़ब कहा गया था बिना सहमति ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा फिर क्यों ड्रोन उड़ाया गया हैं और ज़मीन नहीं देने पर सहमति बनी।

सजल मधु को मिल रही धमकी का मुद्दा उठा, 'मुआवजे के लिए मुर्गा फार्म मत बनाइए'-बैठक के दौरान ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता सजल मधु को कथित रूप से मिल रही धमकियों का मुद्दा भी उठाया। ग्रामीणों ने कहा कि जो लोग स्श्वष्टरु का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अलग-अलग तरीकों से डराने और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक ग्रामीण ने मंच से दावा किया कि कंपनी के जीएम ने कहा है कि कुछ लोग जल्द भूमि अधिग्रहण कराने का आग्रह कर रहे हैं, नहीं तो उनका फार्म गिर जाएगा। इस पर ग्रामीण ने कहा कि ÷सिर्फ अधिक मुआवजा पाने के लिए मुर्गा फार्म जैसे निर्माण खड़े मत कीजिए, गांव और जमीन के भविष्य को प्राथमिकता दीजिए।÷

ड्रोन सर्वे पर फिर उठे सवाल, 'बिना सहमति क्यों उड़ाया गया ड्रोन?'-बैठक में ग्रामीणों ने हाल ही में हुए ड्रोन सर्वे का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया। उनका कहना था कि पूर्व में प्रशासन और कंपनी की बैठक में स्पष्ट कहा गया था कि ग्रामीणों की सहमति के बिना ड्रोन सर्वे नहीं कराया जाएगा। इसके बावजूद आबादी और प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाया गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में पहले थाना में शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है और अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है।

भीम बैरागी और आशीष विश्वास ने गिनाए खदान के नुकसान, हाईकोर्ट जाने पर बनी सहमति-बैठक में भीम बैरागी और आशीष विश्वास ने मंच से कोयला खदान परियोजना के संभावित दुष्प्रभावों को विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि खनन से पर्यावरण, जल स्रोत, खेती और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। वक्ताओं ने कहा कि विकास के नाम पर गांवों के अस्तित्व से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी जारी रही तो मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी।

किसान की जमीन के सामने बना दिया कचरा डंप यार्ड,बेबस अन्नदाता ने लगाई न्याय की गुहार, नगर पंचायत की लापरवाही से खेती पर संकट

घरघोड़ा/मूक पत्रिका

एक ओर सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को सुरक्षित बनाने की बात करती है, तो दूसरी ओर नगर पंचायत की लापरवाही किसानों के लिए नई मुसीबत बनती जा रही है। निजी कृषि भूमि के ठीक सामने नगर पंचायत द्वारा कचरा डंप किए जाने से एक किसान की खेती और पर्यावरण दोनों खतरे में पड़ गए हैं। अब किसान ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।घरघोड़ा नगर पंचायत वार्ड 06 के किसान अजय उरॉव, पिता प्रकाश उरॉव, ने आरोप लगाया है कि उनकी निजी कृषि भूमि खसरा क्रमांक 149/1 एवं 145/1 के सामने नगर पंचायत द्वारा घरेलू एवं प्लास्टिक कचरा, साथ ही बगमुड़ा तालाब से निकाली गई जलकुंभी और गाद बड़े पैमाने पर डंप की जा रही है। किसान का कहना है कि खेत के सामने बने इस अस्थायी कचरा डंप यार्ड से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है, दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है तथा बारिश में कचरा बहकर खेत में पहुंचने से फसल को भारी नुकसान होने की आशंका है। प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान ने प्रशासन से मांग की है कि खेत के सामने जमा कचरे और जलकुंभी को तत्काल हटाया जाए, भविष्य में निजी कृषि भूमि के पास कचरा फेंकने पर रोक लगाई जाए तथा इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित एजेंसी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि अन्नदाता की इस गुहार पर प्रशासन कितनी जल्दी संज्ञान लेकर राहत देता है, या फिर किसान को अपनी ही जमीन बचाने के लिए लंबी लड़ाई लडनी पड़ेगी।

सुनील इस्पात, महालक्ष्मी कास्टिंग, वेजरान इंडस्ट्रीज के दो प्लांट, ओम श्री रुपेश स्टील, रीयल वायर कंपनी की वाहनों की आवाजाही से रोड हुआ खतरनाक

चिराईपानी–गेरवानी पहुंच मार्ग की दुर्दशा से भड़के ग्रामीण करेंगे आंदोलन

रायगढ़/मूक पत्रिका

जिले के ग्राम पंचायत लाखा के चिराईपानी-गेरवानी पहुंच मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर गुजरे जुलाई 2025 में आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम किया था। हालांकि, जनाक्रोश को देख प्रशासन के समक्ष जिम्मेदार कंपनियों ने 1 माह में बनाने का लिखित आश्वासन जरूर दिया था। अब जुलाई 2026 आ गया, लेकिन हालात जस के तस हैं। सूखे दिनों में धूल खाये अब बारिश में कीचड़ की मार झेल रहे लोगों की परेशानी को देखकर भी जनप्रतिनिधि और नेता क्यों चुप्पी साधे हैं। क्या यही दिन देखने के लिए जनता अपना उम्मीदवार चुनती है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में आधे दर्जन कंपनियों के वाहनों की रेलमपेल के चलते रोड की दुर्दशा से भड़के ग्रामीण अब आंदोलन का मूड बना रहे हैं।एक कहावत है ÷सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुँह काला÷ लेकिन भ्रष्टाचार के जमाने में यह कहावत लुप्त होती नजर आ रही है। जमीनी हकीकत यह है कि दिखने में भरोसेमंद लोग ही झूठा वादा कर अपनी-अपनी रोटियाँ सेंकने में मशगूल हैं और पीड़ित जनता पहाड़ पर बैठे बन्दर की तरह टुकुर-टुकुर ताकने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत लाखा की। इसके आश्रित ग्राम चिराईपानी से गेरवानी पहुँच मार्ग की हालत बेहद खराब हो चुकी है। इस मार्ग से जुड़े कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। इनमें सुनील इस्पात एन्ड पॉवर लिमिटेड, महालक्ष्मी कास्टिंग, वेजरान इंडस्ट्रीज के दो प्लांट, ओम श्री रुपेश स्टील, रीयल वायर आदि कम्पनियाँ प्रमुख हैं। यहाँ भारी-भरकम वाहनों की आवाजाही से इस कच्चे सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गयी है। बता दें कि, ग्रामीणों के आने-जाने का यही एकमात्र रास्ता है। बीते साल 2025 के जुलाई महीने में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामवासियों ने आर्थिक नाकेबंदी की थी। घंटों जाम के बाद प्रशासन हरकत में आया और तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार अनुराधा पटेल मौके पर पहुँची। सभी कंपनियों के प्रतिनिधि भी पहुँचे और बातचीत के बाद कम्पनियों द्वारा 1 माह के भीतर सड़क बनाकर देने का आश्वासन दिया गया। वहीं, सड़क किनारे जहाँ-तहाँ ट्रकें खड़ी कर दिए जाने की शिकायत पर तहसीलदार मैडम ने फटकार लगाते हुए वाहनों को अपने ङ्क अपने पार्क में लगाने को कहा और वहाँ मौजूद पुलिस को चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष दिए गए आश्वासन पर ग्रामीणों ने भरोसा करते हुए आंदोलन समाप्त कर दिया, लेकिन तय समय गुजर जाने के बाद भी कंपनियों की ओर से सड़क निर्माण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई।चिराईपानी-गेरवानी पहुंच मार्ग की दुर्दशा से भड़के ग्रामीण करेंगे आंदोलनसुनील इस्पात, महालक्ष्मी कास्टिंग, वेजरान इंडस्ट्रीज के दो प्लांट, ओम श्री रुपेश स्टील, रीयल वायर कंपनी की वाहनों की आवाजाही से रोड हुआ खतरनाकरायगढ़ =जिले के ग्राम पंचायत लाखा के चिराईपानी-गेरवानी पहुंच मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर गुजरे जुलाई 2025 में आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम किया था। हालांकि, जनाक्रोश को देख प्रशासन के समक्ष जिम्मेदार कंपनियों ने 1 माह में बनाने का लिखित आश्वासन जरूर दिया था। अब जुलाई 2026 आ गया, लेकिन हालात जस के तस हैं। सूखे दिनों में धूल खाये अब बारिश में कीचड़ की मार झेल रहे लोगों की परेशानी को देखकर भी जनप्रतिनिधि और नेता क्यों चुप्पी साधे हैं। क्या यही दिन देखने के लिए जनता अपना उम्मीदवार चुनती है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में आधे दर्जन कंपनियों के वाहनों की रेलमपेल के चलते रोड की दुर्दशा से भड़के ग्रामीण अब आंदोलन का मूड बना रहे हैं।

एक कहावत है ÷सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुँह काला÷ लेकिन भ्रष्टाचार के जमाने में यह कहावत लुप्त होती नजर आ रही है। जमीनी हकीकत यह है कि दिखने में भरोसेमंद लोग ही झूठा वादा कर अपनी-अपनी रोटियाँ सेंकने में मशगूल हैं और पीड़ित जनता पहाड़ पर बैठे बन्दर की तरह टुकुर-टुकुर ताकने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत लाखा की। इसके आश्रित ग्राम चिराईपानी से गेरवानी पहुँच मार्ग की हालत बेहद खराब हो चुकी है। इस मार्ग से जुड़े कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। इनमें सुनील इस्पात एन्ड पॉवर लिमिटेड, महालक्ष्मी कास्टिंग, वेजरान इंडस्ट्रीज के दो प्लांट, ओम श्री रुपेश स्टील, रीयल वायर आदि कम्पनियाँ प्रमुख हैं। यहाँ भारी-भरकम वाहनों की आवाजाही से इस कच्चे सड़क की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गयी है। बता दें कि, ग्रामीणों के आने-जाने का यही एकमात्र रास्ता है।

बीते साल 2025 के जुलाई महीने में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामवासियों ने आर्थिक नाकेबंदी की थी। घंटों जाम के बाद प्रशासन हरकत में आया और तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार अनुराधा पटेल मौके पर पहुँची। सभी कंपनियों के प्रतिनिधि भी पहुँचे और बातचीत के बाद कम्पनियों द्वारा 1 माह के भीतर सड़क बनाकर देने का आश्वासन दिया गया। वहीं, सड़क किनारे जहाँ-तहाँ ट्रकें खड़ी कर दिए जाने की शिकायत पर तहसीलदार मैडम ने फटकार लगाते हुए वाहनों को अपने ङ्क अपने पार्क में लगाने को कहा और वहाँ मौजूद पुलिस को चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष दिए गए आश्वासन पर ग्रामीणों ने भरोसा करते हुए आंदोलन समाप्त कर दिया, लेकिन तय समय गुजर जाने के बाद भी कंपनियों की ओर से सड़क निर्माण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हुई।

संपादकीय

सड़कों से संसद तक गूंजा स्टूडेंट्स का आक्रोश, समाधान कब?

संसद का काम जनहित से जुड़े मसलों पर मंथन कर उन्हें निर्णायक रूप देने का होता है, मगर जब सदन में कोई कामकाज ही नहीं होगा, तो फिर उसके मूल उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो पाएगी। प्रवेश परीक्षाओं की प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने का मुद्दा अब सड़क से लेकर संसद तक पहुंच गया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष इस मसले को जोर-शोर से उठा रहा है। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।यह सच है कि देश का संविधान हर नागरिक को इजाजत देता है कि वह शासन-प्रशासन या किसी संस्था की नीतियों और निर्णयों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना असंतोष और मांग जाहिर कर सकता है। ऐसे में क्या वजह रही कि प्रदर्शन कर रहे युवाओं से संवाद के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग करने को ही अंतिम विकल्प मान लिया गया !क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग पर विचार किया जाए और समाधान का कोई रास्ता निकाला जाए? यही नहीं, संसद में इस मुद्दे पर बने गतिरोध से जो कीमती समय बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? संसद का काम जनहित से जुड़े मसलों पर मंथन कर उन्हें निर्णायक रूप देने का होता है, मगर जब सदन में कोई कामकाज ही नहीं होगा, तो फिर उसके मूल उद्देश्य की पूर्ति कैसे हो पाएगी। दरअसल, नीट में गड़बड़ियों को लेकर काकरोच जनता पार्टी (काजपा) की ओर से जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रवेश परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं।इस मामले ने बीते शनिवार को तब तूल पकड़ा, जब बीस दिनों से अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसे युवाओं के आंदोलन की आवाज को दबाने के प्रयास के रूप में देखा गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान सुरक्षा बलों के बल प्रयोग से स्थिति बिगड़ गई और कई जगह दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। मगर अहम सवाल यह है कि यह नौबत आने ही क्यों दी गई? सरकार ने समय रहते प्रदर्शनकारी युवाओं से बातचीत कर उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश क्यों नहीं की? जाहिर है, अगर सरकार की ओर से यह पहल की जाती, तो प्रदर्शनकारियों के संसद तक मार्च को टाला जा सकता था। प्रदर्शनकारी युवा अब भी जंतर-मंतर पर डटे हुए हैं और वे अपनी मांगों पर अडिग हैं। वहां ज्यादा भीड़ जमा न हो, इसके लिए बुधवार को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सत्रह स्टेशनों को बंद कर दिया। मगर इसका खमियाजा उन सैकड़ों यात्रियों को भी भुगतना पड़ा, जो अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए मेट्रो से सफर करते हैं।

शतकीय यात्रा पर भारतीय प्रसारण

आज का दिन भारतीय प्रसारण के इतिहास में विशेष महत्व है। ठीक 99 साल पहले 23 जुलाई 1927 को मुंबई में भारत में पहले व्यवस्थित और संस्थानिक प्रसारण की शुरूआत हुई थी। इस लिहाज से भारतीय प्रसारण आज से अपनी शतकीय सोपान की ओर बढ़ रहा है। इस शतकीय यात्रा में रेडियो की तकनीक में बहुत बदलाव हुआ है। पारंपरिक मीडियम वेब से लेकर शॉर्ट वेब होते हुए रेडियो अब एफएम यानी फ्री[́सी मॉड्यूल के साथ ही डिजिटल दौर में प्रवेश कर गया है। मीडिया के चरित्र में भी सौ साल में बहुत बदलाव हो गया है, लेकिन रेडियो आज भी संवाद और मनोरंजन के सहज संचार माध्यम के रूप में जिंदा है। आसानी से हर जगह उपलब्धता और विशेष तकनीक की वजह से आपदा के क्षणों में संचार के दूसरे माध्यमों की तुलना में रेडियो अब भी सबसे ज्यादा प्रभावी माध्यम बना हुआ है।

(उमेश चतुर्वेदी)

इसे संयोग ही कहेंगे कि जब रेडियो प्रसारण तकनीक का आविष्कार हुआ, उन दिनों देश गुलामी की जंजीरों से बंधा था। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में भी प्रसारण की प्रेरणा ब्रिटेन से मिली। रेडियो प्रसारण तकनीक के विकास के साथ ही 1922 में बीबीसी का गठन हो चुका था।

आज का दिन भारतीय प्रसारण के इतिहास में विशेष महत्व है। ठीक 99 साल पहले 23 जुलाई 1927 को मुंबई में भारत में पहले व्यवस्थित और संस्थानिक प्रसारण की शुरूआत हुई थी। इस लिहाज से भारतीय प्रसारण आज से अपनी शतकीय सोपान की ओर बढ़ रहा है। इस शतकीय यात्रा में रेडियो की तकनीक में बहुत बदलाव हुआ है। पारंपरिक मीडियम वेब से लेकर शॉर्ट वेब होते हुए रेडियो अब एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल के साथ ही डिजिटल दौर में प्रवेश कर गया है। मीडिया के चरित्र में भी सौ साल में बहुत बदलाव हो गया है, लेकिन रेडियो आज भी संवाद और मनोरंजन के सहज संचार माध्यम के रूप में जिंदा है। आसानी से हर जगह उपलब्धता और विशेष तकनीक की वजह से आपदा के क्षणों में संचार के दूसरे माध्यमों की तुलना में रेडियो अब भी सबसे ज्यादा प्रभावी माध्यम बना हुआ है। समुद्री तूफानों, सुनामी, कश्मीर घाटी की बाढ़ आदि मौकों पर संवाद के लिए रेडियो ने अपनी ताकत और उपादेयता को बार-बार साबित किया है। देश से माओवादी और नक्सली आतंक का खात्मा हो चुका है, लेकिन एक दौर में विशेषकर बस्तर के नक्सली इलाकों में नक्सलियों से संवाद के लिए रेडियो का ही इस्तेमाल किया जाता था। इसे संयोग ही कहेंगे कि जब रेडियो प्रसारण तकनीक का आविष्कार हुआ, उन दिनों देश गुलामी की जंजीरों से बंधा था। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में भी प्रसारण की प्रेरणा ब्रिटेन से मिली। रेडियो प्रसारण तकनीक के विकास के साथ ही 1922 में बीबीसी का गठन हो चुका था। हालांकि ब्रिटेन में इसके पहले ही निजी और शौकिया प्रसारण की शुरूआत हो चुकी थी। इसका असर भारत पर भी पड़ा। भारत में भी 1920 से 1926 के बीच तत्कालीन बंबई और कलकत्ता में रेडियो क्लबों की शुरूआत हुई। उन क्लबों ने अपने तरीके से प्रसारण के किंचित सफल और ज्यादातर असफल प्रयास भी किये। उन दिनों भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इर्विन थे। अखबारों की तुलना में रेडियो प्रसारण की अहमियत और प्रभाव को इर्विन समझते थे। शायद यही वजह रही कि भारत में 1926 में गठित इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का गठन हुआ। कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक बांबे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने जून 1923 में पहला रेडियो प्रसारण किया। इसके करीब पांच महीने बाद नवंबर 1923 में कलकत्ता रेडियो क्लब की स्थापना हुई। ऐसे ही प्रयास तत्कालीन मद्रास में भी हुए। लेकिन पहला व्यवस्थित और संस्थानिक रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने 23 जुलाई 1927 को मुंबई से किया था। इसी वजह से भारत हर साल 23 जुलाई को प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके महीनेभर बाद 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता से बांग्ला में प्रसारण शुरू हुआ।

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी छह लाख की पूंजी से शुरू की गई थी। कंपनी ने रेडियो प्रसारण के लिए अंग्रेज सरकार से 13 सितंबर 1926 को करार हुआ, जिसके तहत उसने प्रसारण शुरू किया। कंपनी को पूंजी में से साढ़े चार लाख दोनों रेडियो केंद्रों की स्थापना में ही खर्च हो गए। तब आमदनी का स्रोत रेडियो लाइसेंस फीस थी, जो प्रति रेडियो दस रूपए थी। बहुत कोशिशों के बावजूद सिर्फ आठ हजार ही लाइसेंस दिए जा सके। तब प्रसारण डेढ़-डेढ़ किलोवाट के ट्रांसमीटरों से बमुश्किल तीस मील के ही दायरे में हो पा रहा था, लिहाजा रेडियो का प्रसार नहीं बढ़ा। कंपनी को रेडियो प्रसारण के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही थी। लिहाजा यह कंपनी 1930 में ही बंद हो गई। भारत में आधुनिक प्रसारण की ठोस बुनियाद

रखने का श्रेय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो और ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कंपनी के पूर्व प्रसारक लायनेड फील्डेन को जाता है। लिनलिथगो की पहल पर उद्योग और श्रम विभाग के अधीन अप्रैल 1930 में इंडियन स्टेट ब्राडकास्टिंग सर्विस की शुरूआत हुई। इसे रेडियो प्रसारण को नया रूप देना था। इसके बाद अगस्त 1935 में लायनेड फील्डेन को इस सर्विस का कंट्रोलर नियुक्त किया गया। फील्डेन को यह नाम पसंद नहीं आ रहा था। फील्डेन ने अपनी पुस्तक 'नेचुरल बेंट' में लिखा है कि उन्होंने लिनलिथगो को सुझाया कि ब्रॉडकास्टिंग शब्द कठिन है, जो आसानी से भारतीयों की जुबान पर नहीं चढ़ पाएगा। फिर यह नाम भारत सरकार अधिनियम के अनुकूल नहीं है। लिहाजा उन्होंने इसे 'ऑल इंडिया रेडियो' करने का सुझाव दिया। जिसे लिनलिथगो ने स्वीकार कर लिया। इसी के बाद आठ जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से दिल्ली के अलीपुर के छह कमरों के एक घर से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। कुछ महीने बाद यह दफ्तर दिल्ली के संसद मार्ग स्थित नए बने प्रसारण भवन में आया और तब से लेकर अब तक दिल्ली केंद्र का प्रसारण वहीं से हो रहा है।

तीन मई 2023 से ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के नाम से जाना जा रहा है। वैसे ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम गांधी जयंती के दिन 1957 में दिया गया, जिसे अगले दिन से लागू किया गया। आकाशवाणी का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में आकाश से आने वाली आवाज या देववाणी के रूप में मिलता है। वैसे आकाशवाणी के नाम से मैसूर के विद्वान एमवी गोपालस्वामी ने 10 सितंबर 1935 से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। यह प्रसारण केंद्र मैसूर राजमहल से कुछ सौ मीटर दूर स्थित है। आकाशवाणी का जिक्र 1938 में कलकत्ता में शॉर्ट वेब के प्रसारण की शुरूआत के वक्त भी हुआ। तब प्रसारण के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने गुरूदेव रवींद्र नाथ टैगोर से एक कविता मांगी थी। टैगौर ने बांग्ला की जो कविता दी, उसमें रेडियो के लिए आकाशवाणी शब्द का प्रयोग हुआ है।

इसे संयोग ही कहेंगे कि जिस समय देश में रेडियो का विस्तार हो रहा था, उन्हीं दिनों स्वाधीनता आंदोलन चरम पर था। उसी दौरान 1942 में डॉक्टर राममनोहर लोहिया और ऊषा मेहता की अगुआई में मुंबई से कांग्रेस रेडियो और रंगून से सुभाष चंद्र बोस ने आजाद रेडियो का प्रसारण शुरू किया। बोस जहां अपने रेडियो के जरिए भारतीय जनता से संवाद कर रहे थे, वहीं कांग्रेस रेडियो भूमिगत ढंग से चलाया जा रहा था। जिसके जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को सूचनाएं दी जा रही थीं। उन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार ने देश में नौ रेडियो प्रसारण केंद्र स्थापित किए। ये केंद्र दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, त्रिचिरापल्ली, चेन्नई, ढाका, पेशावर और लाहौर में थे। बंटवारे के बाद भारत के हिस्से छह रेडियो स्टेशन आए, जबकि पाकिस्तान को ढाका, पेशावर और लाहौर स्टेशन मिले। आजादी के बाद देश के पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सरदार पटेल को मिली। उन्हें रेडियो की महत्ता का भान था। इसीलिए उन्होंने रेडियो के तेज विकास की नींव रखी। आजादी के बाद पहला रेडियो स्टेशन 16 जुलाई 1948 को शुरू हुआ। जिसका उद्घाटन पटेल ने किया था। स्वाधीन भारत में रेडियो का चरित्र और लक्ष्य क्या होगा, इसका संकेत सरदार पटेल के उस उद्घाटन भाषण में दिखता है। सार्वजनिक प्रसारक के रूप में रेडियो के लक्ष्य को एक तरह से मद्रास प्रांत के तत्कालीन प्रीमियर सी राजगोपालाचारी ने 1938 में ही रख दिया था। 16 जून 1938 को मद्रास रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करते हुए राजगोपालाचारी ने रेडियो को लोक जागरण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया था। इसके साथ ही उन्होंने संचार के तेज माध्यम के रूप में रेडियो का शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए करने पर जोर दिया था। यहां यह बताना जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक प्रसारक के रूप में रेडियो आज भी यह भूमिका बखूबी निभा रहा है। भारतीय इतिहास में रेडियो कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है। तीन जून 1947 को भारत विभाजन की योजना की देश को जानकारी रेडियो के जरिए ही मिली। तब माउंट बेटन, नेहरू, जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह ने रेडियो के ही माध्यम से अपने विचार रखे थे। 14-15 अगस्त 1947 की दरम्यानी रात को भारत की आजादी के बाद नेहरू के प्रसिद्ध भाषण 'ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' को देश ने रेडियो के जरिए सुना था।

तत्काल स्वास्थ्य लाभ के चक्कर में डॉक्टर शॉपिंग का नया चलन

(डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा)

डॉक्टर शापिंग के इस दौर में अन्य चिकित्सक की विशेषज्ञ सलाह लेने और चिकित्सक बदलने में हमें अंतर करना होगा। अन्य विशेषज्ञ की सलाह को तो ईलाज कर रहे चिकित्सक को विश्वास में लेकर लेने से ईलाज में और अधिक सकारात्मकता आती है पर बार बार चिकित्सक बदलना उचित नहीं माना जा सकता।

समय के साथ सोच में एक बड़ा बदलाव तेजी से यह देखने में आ रहा है कि यदि जुखाम, बुखार, खांसी जैसी सामान्य बीमारी में भी डॉक्टर की दवा से तत्काल राहत नहीं मिलती तो अब डॉक्टर बदलने में कोई गुरेज नहीं होता। देखा जाएं तो तुरंत स्वास्थ्य लाभ की प्रवृति के कारण डॉक्टर के ईलाज पर विश्वास में कहीं ना कहीं कमी देखने में आने लगी है और इसके परिणाम स्वरुप महानगरों में डॉक्टर शापिंग का नया ही चलन चलने लगा है। खासतौर से मरीज से मिलने-मिलाने वाले चिकित्सक बदलने की सलाह देने में किसी तरह का कोई गुरेज नहीं करते। चिकित्सक बदलने में कोई बुराई नहीं है पर जिस चिकित्सक से ईलाज करवा रहे हैं उससे बीमारी ठीक होने की संभावना के संबंध में चर्चा करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अन्य चिकित्सक की सलाह लेना और चिकित्सक बदलने में हमें अंतर करके चलना होगा। बीच ईलाज ही बार बार डाक्टर बदलने के कई साइड इफेक्ट से भी दो चार होना पड़ता है और कई बार तो डॉक्टर बदलने का यह प्रयोग ईलाज पर विपरीत प्रभाव और गंभीर संकट में डाल देता है। मिसाल के तौर पर सामान्य खांसी की बीमारी या पेट में गड़बड़ या वाइरल बुखार होने पर जब डॉक्टर द्वारा दवा का जो कोर्स दिया जाता है उसके पूरा होने के पहले ही यानी की मान लो पांच दिन का कोर्स दिया है तो तीसरे दिन ही अधीर होकर दूसरे डॉक्टर की शरण में जाना आम होता जा रहा है। हांलाकि यह प्रवृति कुछ ही लोगों में है पर महानगरों और बड़े शहरों में इस तरह की प्रवृति जिस तेजी से बढ़ती जा रही है वह गंभीर चिंता का सबब बनती जा रही है। चिकित्सकीय भाषा में कहा जाए तो यह प्रवृति शापिंग का एक नया रुप डॉक्टर शापिंग के रुप में तेजी से फैलती जा रही है। हो यह रहा है कि इसके साइड इफेक्ट से अनजान होकर आगे बढ़ रहे है।

डॉक्टर शापिंग का कंसेप्ट बीसवीं सदी में नशीली दवाओं की प्राप्ति के लिए किये जाने वाले प्रयासों के लिए चलन में आया था। नशीली दवाओं के आदतन लोग एक से दूसरे डॉक्टर के पास परचा लिखवाने इसलिए जाते थे ताकि नशीली दवाओं का संग्रह कर सके। क्योंकि नशीली दवा एक सीमा तक ही मिलती थी और बिना चिकित्सक के परचे के मिलना लगभग मुश्किल होता था। यही कारण है कि देश और विदेश में नित नए डॉक्टर से परचा लिखवाना और केमिस्ट से दवा प्राप्त करना आम होता जा रहा था। खासतौर से रोक वाली दवाओं को लेकर के यह प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। हांलाकि इस प्रवृति को रोकने के लिए कई देशों में कानूनी प्रयास किये गए और कुछ हद तक इस पर अंकुश भी लग सका। अमेरिका जैसे देश में इसके लिए डॉक्टर शापिंग लॉ जैसी व्यवस्था की गई। खैर अब चिकित्सा सुविधा के विस्तार और सहजता के साथ ही डॉक्टर शापिंग का कंसेप्ट बदलता जा रहा है।

हो यह रहा है कि जब कोई मरीज यह महसूस करता है कि चिकित्सक की दवा से उसकी बीमारी में तेजी से सुधार नहीं हो रहा तो वह ईलाज के बीच ही दूसरे डॉक्टर की शरण में चले जाता है। खासतौर से यह प्रवृति महानगरों और बड़े शहरों में अधिक तेजी से फैल रही है। इसका कारण यह है कि आज सलाहकारों की लंबी फौज होने के साथ ही रोगी या रोगी के परिजन मैजिक टच की सोच रखने लगे हैं। दूसरा यह कि अब चिकित्सा सुविधा का भी तेजी से विस्तार हुआ है। निजी और सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा की सहज उपलब्धता होने के साथ ही मेडिक्लेम जैसी सुविधाएं प्राप्त होने लगी है। सरकारी और निजी विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता के कारण भी यह होने लगा है। बीमारी चाहे सामान्य हो या गंभीर तत्काल सुधार नहीं दिखने पर दूसरे डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं और डाक्टर बदलने का तत्काल जो प्रभाव पड़ता है वह रीसेट बटन होता है यानी कि दूसरा डॉक्टर फिर अपने तरीके से पहले जॉचों का सिलसिला आरंभ करते हैं क्योंकि पहले की डॉक्टर द्वारा कराई गई जांचों में किसी ना किसी तरह की कमी या अन्य कारण बता कर दुबारा से जांचें करवानी पड़ती है। इसके लिए रक्त जांच से लेकर रोग के अनुसार एक्सरे, एमआरआई या अन्य तरह की जांचें भी हो सकती है। इससे बार बार जांच और एक्सरे किरणों से दो चार होने के साथ ही रुपये पैसे का भार भी पड़ता है। एक तरह से बीमारी के पहचान की नए सिरे से प्रक्रिया आरंभ होती है। दवा का नया सिलसिला आरंभ होता है और पूर्व में चल रही एंटिबायोटिक या अन्य दवाओं के स्थान पर जेनेरिक दवाओं के ही दूसरे ब्राण्ड की दवा दी जाती है व कई बार तो पॉली फार्मेसी जैसी स्थिति हो जाती है। दवाओं के असर पर विपरीत प्रभाव की संभावनाओं से भी नहीं नकारा जा सकता। ऐसे में सुधार के स्थान पर जटिलताओं की संभावनाओं से नहीं नकारा जा सकता।

सरोगेसी के बहाने चल रहे कारोबार पर सरकार का बड़ा प्रहार, नए नियमों से बढ़ेगी पारदर्शिता

भारत दुनिया भर के दंपतियों के लिए किराए की कोख का एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनता जा रहा है। दरअसल, जो सुविधा वास्तविक जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई थी, वह अमीर दंपतियों के लिए शौक में बदलती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के बाद भारत में प्रजनन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसमें किराए पर कोख दिए जाने का व्यवसाय भी शामिल है। चिकित्सा पर्यटन के बहाने विदेशी पर्यटक प्रसूति पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं। यह तथ्य है कि पिछले कुछ बरसों में देश में कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या 35 से 50 फीसदी बढ़ गई है। इसी अनुपात में कृत्रिम गर्भाधान के नाम पर जालसाजी बढ़ी है।

(प्रमोद भार्गव)

कृत्रिम गर्भाधान ने आज जिस तरह व्यवसाय का रूप ले लिया है, वह चिंता का विषय है। मगर अब केंद्र सरकार 'किराए की कोख' के नाम पर चल रहे कारोबार पर अंकुश लगाने जा रही है। इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि किराए की कोख उपलब्ध कराने के नाम पर चल रही मनमानी पर लगाम लगेगी।

दरअसल, 'सरोगेसी सेंटरों' में काफी समय से चल रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने इसमें पंजीयन और संचालन नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत इन केंद्रों को नियंत्रित किया जाएगा। अब किराए की कोख के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। इनकी कड़ी निगरानी होगी। कागजी आवेदन करने की सुविधा प्रतिबंधित कर दी गई है। 'सरोगेसी क्लीनिक' जरूरतमंद लोगों को इतनी सहजता से यह सुविधा नहीं दे सकेंगे। केंद्र सरकार ने नए नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं।

किराए की कोख के कानून में परिवर्तन इसके बढ़ते व्यापार पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। अब केवल निसंतान दंपति, जो बच्चे पैदा करने में शारीरिक रूप से अक्षम हैं, वे अपने किसी करीबी रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। इस सुविधा को कानूनी भाषा में 'अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी' कहा जाता है।

भारत दुनिया भर के दंपतियों के लिए किराए की कोख का एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र बनता जा रहा है। दरअसल, जो सुविधा वास्तविक जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई थी, वह अमीर दंपतियों के लिए शौक में बदलती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार के बाद भारत में प्रजनन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इसमें किराए पर कोख दिए जाने का व्यवसाय भी शामिल है। चिकित्सा पर्यटन के बहाने विदेशी पर्यटक प्रसूति पर्यटन के लिए भी आ रहे हैं।

यह तथ्य है कि पिछले कुछ बरसों में देश में कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या 35 से 50 फीसदी बढ़ गई है। इसी अनुपात में कृत्रिम गर्भाधान के नाम पर जालसाजी बढ़ी है। हैदराबाद में ऐसा गिरोह पकड़ा गया, जो दो लाख से चार लाख रुपये में कोख किराए पर लेकर उसे 30 लाख रुपये तक में बेच देता था। यहां तक कि विदेश से भी शुक्राणु दानदाता लाए गए। यानी देश के बाहर भी बच्चे बेचे गए।

हालांकि, वर्ष 2025 में सरकार ने शुक्राणु दाता नियमों में बदलाव किया था, लेकिन कारोबारियों ने नियमों की अनदेखी की। नाबालिग और अविवाहित लड़कियों की कोख का भी अवैध इस्तेमाल किया गया। भारत में कोख किराए पर लेने का खर्च 10 से 25 लाख रुपये है, जबकि विदेश में 80 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक है। इसलिए 'सरोगेसी क्लीनिक' में किराए की कोख अवैध कारोबार का बड़ा धंधा बनती जा रही है।

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु में अनेक मामले सामने आए, जिनमें ठगी की गई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार को नियमों में बदलाव करना पड़ा। इसके पहले 2025 में समलैंगिक युगलों को किराए की कोख के जरिए माता-पिता बनने का अधिकार देने से मना कर दिया गया था।

अब ऑनलाइन जानकारी होने से निगरानी तंत्र के पास कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के संचालन और नवीनीकरण संबंधी जानकारी हर वक्त सामने होगी। इससे अनियमितता को आसानी से चिह्नित कर लिया जाएगा। क्लीनिक के पास वैध दस्तावेज हैं या नहीं, इसकी भी पुख्ता जानकारी मिलती रहेगी। कोई भी कमी पाए जाने पर संस्था को प्रतिबंधित किया जा सकेगा। इन केंद्रों में कर्मचारियों से लेकर बच्चों के जन्म तक की जानकारी मिलती रहेगी।

सरकार इन नियमों को एक साथ लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से अमल में लाएगी। वर्तमान कानून के अनुसार किसी अन्य महिला की कोख के लिए अनुमति तब मिलती है, जब कानून के अनुसार विवाहित जोड़ा शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर गर्भधारण करने में पत्नी की जान को खतरा हो। यानी इस स्थिति में वैवाहिक जोड़ा किराए की कोख की मदद ले सकता है।

कानून के अनुसार यह भी बाध्यकारी शर्त है कि किराए की कोख देने वाली महिला एक तो विवाहित होनी चाहिए और दूसरे, कम से कम उसका एक बच्चा भी हो। पति की आयु 26 से 55 वर्ष और पत्नी की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच होना जरूरी है।

भारत में किराए की कोख का कारोबार अरबों डॉलर का हो गया है, लेकिन यह धंधा अंततः स्त्री की कोख पर टिका है। ठीक उसी तरह, जिस तरह उदारवादी अर्थव्यवस्था प्रकृति के गर्भ में समाई खनिज संपदाओं के दोहन पर टिकी है। इस व्यवसाय की कीमत उन महिलाओं को चुकानी पड़ी है, जिन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए हर हाल में धन की जरूरत रहती है। इसलिए वर्ष 2016 में प्रजनन सहायक तकनीक विधेयक लाकर केंद्र सरकार ने इस गोरखधंधे पर लगाम लगाने की पहल कर दी थी। मगर इस कानून से उन्हें परेशानी है, जिन्होंने स्त्री की आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी कोख को बाजार के हवाले कर दिया है। वे यह भी दलील दे रहे हैं कि कठोर कानून से विदेशी मुद्रा का आगमन रुक जाएगा।

गौरतलब है कि जैविक माता-पिता के शुक्राणु और अंडाणु को परखनली में निषेचित करने के बाद जब भ्रूण पनप जाता है, तब उसे अन्य स्त्री की कोख में प्रत्यारोपित किया जाता है। गर्भाधान का यही तरीका अपनाया जाता है। मगर इसका शरीर पर विपरीत असर पड़ता है। इसके गर्भपात होने की 80 फीसदी आशंका रहती है। ऐसी 90 फीसदी प्रसूतियां शल्य क्रिया के जरिए होती हैं। ऐसे में महिला की जान का जोखिम भी बना रहता है। कोख किराए पर देने वाली महिला का न तो कोई बीमा होता था, न ही उसके बच्चों की कोई गारंटी लेता था। इस संदर्भ में यह भी बड़ा सवाल था कि जैविक अभिभावक यदि जन्मे बच्चे को छोड़कर भाग जाते हैं।

किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य, कलेक्टर ने जारी किए आदेश बिना सत्यापन मकान किराये पर देने पर होगी कार्रवाई पुराने किरायेदारों की जानकारी भी संबंधित थाने में देना होगा अनिवार्य

भवन स्वामी रखें किरायेदारों का पूरा रिकॉर्ड, संदिग्ध गतिविधि की तत्काल दें सूचना

आमजन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी हुआ आदेश

रायगढ़ /मूक पत्रिका

जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब रायगढ़ जिले के नगरीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मकान किराये पर देने से पूर्व किरायेदार का पुलिस सत्यापन एवं उसकी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने जारी आदेश में कहा है कि यह संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के उद्देश्य से शहरी एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में किराये के मकानों में रह रहे हैं। वहीं अधिकांश भवन स्वामी अपने किरायेदारों एवं घरेलू सहायकों का पुलिस सत्यापन नहीं कराते, जिससे अपराधों की रोकथाम एवं संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने में कठिनाई आती है। इसे देखते हुए व्यापक जनहित में यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार कोई भी भवन स्वामी अथवा प्रतिष्ठान संबंधित थाना प्रभारी को किरायेदार की जानकारी दिए बिना मकान या उसका कोई हिस्सा किराये पर नहीं देगा। यह व्यवस्था नए किरायेदारों के साथ-साथ पहले से रह रहे किरायेदारों पर भी लागू होगी। पुराने किरायेदारों की जानकारी भी संबंधित थाने में तत्काल उपलब्ध करानी होगी। भवन स्वामियों को प्रत्येक किरायेदार का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नंबर तथा वैध पहचान पत्र का विवरण अपने अभिलेख में सुरक्षित रखना होगा। यही जानकारी पुलिस को भी उपलब्ध करानी होगी। बिना वैध एवं प्रामाणिक पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को किराये पर आवास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी किरायेदार अथवा उसके यहां आने-जाने वाले व्यक्ति की गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होती है तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना या पुलिस चौकी को देना अनिवार्य होगा, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के तहत तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार लाउडस्पीकर सहित अन्य माध्यमों से किया जाए। साथ ही इसकी प्रति पुलिस थानों, नगरीय निकायों, कार्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

खरसिया पुलिस की त्वरित कार्रवाई : कूनकुनी ओवरब्रिज पर ट्रकों की टक्कर के बाद मिनटों में संभाला मोर्चा

खरसिया/मूक पत्रिका

स्थानीय क्षेत्र के कूनकुनी ओवरब्रिज के पास उस वक्त अफ़रा-तफ़री मच गई जब दो भारी वाहन (ट्रक) आपस में आमने-सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया और मौके पर लंबे जाम के आसार बन गए थे। हालांकि, गनीमत यह रही कि इस भीषण हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, केवल एक ट्रक चालक को मामूली चोटें आई।

मिनटों में एक्टिव हुई पुलिस

सड़क सुरक्षा और त्वरित पुलिस रिस्पॉन्स को प्राथमिकता देते हुए एसएसपी शशिमोहन सिंह के निर्देशन में खरसिया पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सीताराम ध्रुव अपनी पुलिस टीम के साथ बिना एक पल गंवाए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

यातायात किया गया सामान्य

मौके पर पहुंचते ही पुलिस बल ने सबसे पहले दुर्घटनास्थल को सुरक्षित (स्द्गष्द्वह्ल्द्र) किया। इसके बाद तुरंत क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क के बीच से हटवाया गया। यातायात में आ रही बाधा को दूर करने के लिए मौके पर ही ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था की गई, जिससे पीछे से आ रहे वाहन सुचारू रूप से निकलते रहे। पुलिस की इस तत्परता और सूझबूझ के चलते कूनकुनी ओवरब्रिज पर एक बड़ा ट्रैफिक जाम टल गया और कुछ ही मिनटों के भीतर आवागमन पूरी तरह सामान्य कर दिया गया। फिलहाल, खरसिया पुलिस द्वारा इस संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों और राहुल गांधी के संघर्ष की जीत - विक्रम मंडावी

शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का लगाया आरोप, सख्त कानून बनाने की मांग की

बीजापुर/मूक पत्रिका

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश के करोड़ों छात्रों, युवाओं और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निरंतर संघर्ष का परिणाम बताया है। रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज और अन्याय के खिलाफ हुए आंदोलन ने सरकार को निर्णय लेने के लिए मजबूर किया।

मंडावी ने कहा कि पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हुए पेपर लीक ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि इन घटनाओं से युवाओं की मेहनत और उनके अभिभावकों के सपनों को नुकसान पहुंचा है।

उन्होंने कहा कि जब देश का युवा अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरता है तो सरकारों को भी झुकना पड़ता है।

विधायक ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय उसे लगातार कमजोर किया जा रहा है। उनके अनुसार निजी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा मिलने से आम, गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर शिक्षा का आर्थिक बोझ बढ़ा है, जबकि शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर युवाओं को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।मंडावी ने केंद्र सरकार से मांग की कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं और मजबूत व पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू की जाए, ताकि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रह सके।

24 घंटे में संत माईकेल स्कूल चोरी का पदाफाश, चोरी में शामिल 6 आरोपी और 2 कबाड़ी गिरफ्तार

चोरी के नए वायर जलाकर निकाला तांबा, कबाड़ियों को बेचा; स्कूटी, जले हुए तार और नकदी जब्त

कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई से निर्माणाधीन स्कूल में हुई बड़ी चोरी का खुलासा कर आरोपियों को भेजा रिमांड पर

रायगढ़/मूक पत्रिका

एसएसपी शशि मोहन सिंह के मार्गदर्शन पर कोतवाली पुलिस ने रायगढ़ के रामभांठा स्थित संत माईकेल अंग्रेजी माध्यम स्कूल के निर्माणाधीन भवन से वायरिंग वायर, प्लम्बिंग सामग्री, पेंटिंग सामग्री, तड़ित चालक एवं अन्य निर्माण सामग्री की चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर शानदार सफलता हासिल करते हुए छह आरोपियों एवं चोरी का माल खरीदने वाले दो कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में तीन विधि से संघर्षरत अपचारी बालक भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। स्कूल प्रबंधन की ओर से रोमानुस कुजूर ने 24 जुलाई को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 जुलाई को विद्यालय बंद करने के बाद 20 जुलाई की सुबह जब विद्यालय खोला गया तो निर्माणाधीन भवन के कमरे का ताला टूटा मिला। अंदर रखे वायरिंग वायर, प्लम्बिंग सामग्री, पेंट, पेंट की बाल्टियां, तड़ित चालक सहित अन्य सामग्री गायब थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ?2 लाख थी। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 399/2026 धारा 331(4), 305 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल ने अपराध दर्ज होते ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। विवेचना के दौरान एक ऐसे नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जो पूर्व में भी चोरी की घटनाओं में शामिल रह चुका था। पूछताछ में उसने अपने साथी राहिल एक्का तथा दो अन्य अपचारी बालकों के साथ मिलकर स्कूल में चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि चोरी किए गए नए बिजली के तारों को सुनसान स्थान पर जलाकर उनमें से तांबा निकाला गया और बाद में अपने परिचित अनुज टंडन एवं विजय बंजारे की मदद से स्कूटी में ले जाकर कबाड़ी आशिक रब्बानी और प्रकाश चौहान को बेच दिया। कल आरोपियों की धरपकड़ दौरान आरोपी अनुज टंडन फरार था जिसे आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का विजय मार्च, लोकतंत्र की जीत बताया

बेमेतरा/मूक पत्रिका

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा द्वारा भारत माता चौक से गांधी पार्क तक विजय मार्च एवं सत्याग्रह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों, छात्र-युवा साथियों एवं आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आशीष छाबड़ा ने दावा किया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा छात्र-युवा शक्ति, लोकतंत्र और जनसंघर्ष की ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद के भीतर तथा कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस ने देशभर में सड़क पर छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लगातार उठाया, जिसके परिणामस्वरूप यह स्थिति बनी।छाबड़ा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रही है और आगे भी जनहित के मुद्दों पर मजबूती से आवाज़ उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि यह विजय देश के उन करोड़ों छात्रों और युवाओं की है जिन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया।उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके संघर्ष ने युवाओं को अपनी आवाज़ बुलंद करने का साहस दिया है। साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए गए जनजागरण अभियान, धरना-प्रदर्शन और लोकतांत्रिक आंदोलनों की भी प्रशंसा की।कार्यक्रम के अंत में आशीष छाबड़ा ने विजय मार्च में शामिल सभी छात्र-युवा साथियों, कांग्रेसजनों, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कांग्रेस का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

उल्लास केंद्रों के नियमित संचालन और महापरीक्षा की तैयारियों पर जोर, उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की समीक्षा बैठक संपन्न, संकुल समन्वयकों को दिए आवश्यक निर्देश

बस्तर/मूक पत्रिका

जनपद पंचायत बस्तर में शनिवार को उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विकासखंड बस्तर के एबीईओ एवं उल्लास कार्यक्रम के विकासखंड नोडल अधिकारी सुशील कुमार तिवारी ने की। बैठक में विकासखंड के सभी संकुल समन्वयकों ने भाग लिया।बैठक में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित सभी उल्लास केंद्रों के नियमित संचालन, सतत निरीक्षण एवं प्रभावी मॉनिटरिंग पर विशेष बल दिया गया। आगामी उल्लास महापरीक्षा को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, ताकि कार्यक्रम का सफल संचालन सुनिश्चित किया जा सके।समीक्षा बैठक में विद्यार्थियों के जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र समय पर बनवाने, अंकसूची में त्रुटियों का शीघ्र निराकरण कराने, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए पात्र विद्यार्थियों के आवेदन भरवाने तथा राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति (एनएमएमएस) परीक्षा के लिए चयनित विद्यार्थियों का 30 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पंजीयन कराने पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा वीएसके ऐप में प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने, विनोबा ऐप पर ÷बोलेगा बचपन÷ गतिविधि के वीडियो नियमित रूप से अपलोड करने, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का सुचारु संचालन, विद्यालय एवं शौचालयों की नियमित साफ-सफाई तथा विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।बैठक के अंत में एबीईओ एवं विकासखंड नोडल अधिकारी सुशील कुमार तिवारी ने सभी संकुल समन्वयकों से शासन के निर्देशों का गंभीरतापूर्वक पालन करते हुए विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने, शैक्षणिक गतिविधियों की सतत निगरानी रखने तथा शासन की सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समन्वित प्रयासों से ही विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है।

आरक्षक के पिता ने जताई नाराजगी, उच्च स्तरीय जाँच की मांग।

हसौद थाने के अंदर आरक्षक के आत्महत्या ने पुलिस महकमें पर किए सवाल खड़े

सक्ती/ हसौद/मूक पत्रिका

जिले के हसौद थाना क्षेत्र में शनिवार की बीते रात हुई घटना ने पुलिस महकमे को झकझोर कर रख दिया। हसौद थाने में तैनात एक सिपाही ने थाने के अंदर ही फँसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आरक्षक जय लहरे का शव थाने के ऊपरी मंज़िल के कमरे के खिड़की पर फंदे पर लटकता हुआ मिला। तो वहीं पुलिस आरक्षक की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया व पुलिस कर्मी की आत्महत्या का मामला पूरे क्षेत्र चर्चा का विषय बन गया है। मिले जानकारी के मुताबिक आरक्षक जय लहरे शनिवार 25/07/2026 के शाम 7 बजे के दरमियान थाने भवन के बैरक के खिड़के में लटका हुआ मिला। जिसे देख कर अननफ़न में थाने में मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ले जाया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जहां डाक्टरों ने आरक्षक जय कुमार लहरे को को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आत्महत्या के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।

वर्दी के भीतर का सन्नाटा – हसौद थाने में आरक्षक की आत्महत्या ने खड़े किए सवाल

परिवार में पसरा मातम आत्महत्या के कारण को स्पष्ट पारदर्शिता की माँग करते हुए आरक्षक के पिता शिव लहरे ने बताया की थाने के जिस कमरे के खिड़की में मेरे पुत्र का आत्महत्या करना बताया जा रहा है उसका उचाई लगभग 3 से 4 फिट होगा। साथ ही जिस रस्सी पर फंद्दा लगाने की बात पुलिस कर्मी कर रहे है वो धान की फ़सल को सिलाई करने वाला रस्सी है।जिससे ये साबित नहीं हो पा रहा की फंद्दे पर लटका हुआ कैसे हो सकता है। तो वही मृतक आरक्षक के पिता ने ये भी स्पष्ट तौर पर कहा की जब मेरे पुत्र की उचाई 6 फिट है तो 3-4 फिट में कैसे फाँसी लगा सकता है। साथ ही इन सभी बातों का कोई प्रूफ भी नहीं साबित होने का भी बात शिव लहरे ने कहा। जिससे थाने में मौजूद स्थानीय पुलिस प्रशासन के कर्मियों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है।

वर्दी और दबाव

इस घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को सामने ला दिया है। लगातार ड्यूटी, कम स्टाफ, जनता की उम्मीदें और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां - इन सबके बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। कई बार वर्दी के भीतर का तनाव बाहर नहीं दिखता।

वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। साथ ही विभाग में काउंसलिंग और सहयोग की व्यवस्था पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

जय लहरे की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यह एक परिवार के उजड़ने की कहानी है, और एक सिस्टम को आईना दिखाने वाली घटना भी है।

मेरे बेटे की मौत कैसे हुई, किन कारणों से हुई?

निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई होना चाहिये पुलिस अधिकारियों की घोर लापरवाही है।

शिव लहरे
मृतक के पिताजी

हसौद थाने में पदस्थ आरक्षक जय लहरे थाने के बैरक में ही प्रथम दृष्टया आत्महत्या कर लिया है मामले की जांच की जा रही है जो तथ्य सामने आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पंकज पटेल
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सक्ति

संक्षिप्त समाचार

सफलता की कहानी सामुदायिक डबरी निर्माण से बदली कर्रा गांव की तस्वीर

बिलासपुर। जिले के विकासखंड कोटा अंतर्गत ग्राम पंचायत नवागांव कर्रा के मजौलीपारा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत सामुदायिक डबरी का निर्माण किया गया। इस कार्य का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण, भू-जल स्तर में वृद्धि, सिंचाई सुविधा का विस्तार, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना तथा ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना था। इस कार्य के लिए कुल 5.11 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई। निर्माण कार्य ग्राम पंचायत द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन एवं नियमानुसार मनरेगा के पात्र श्रमिकों के माध्यम से पूर्ण कराया गया। ग्राम के समीप स्थित मुक्तिधाम क्षेत्र में वर्षा जल के उचित संग्रहण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। बरसात का अधिकांश पानी बहकर व्यर्थ चला जाता था, जिससे गर्मी के मौसम में जल संकट, भू-जल स्तर में गिरावट तथा सिंचाई की समस्या बनी रहती थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए सामुदायिक डबरी का निर्माण कराया गया, जिससे वर्षा जल का प्रभावी संचयन संभव हुआ। डबरी निर्माण के बाद आसपास के क्षेत्रों में भू-जल पुनर्भरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। खेतों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने लगा, जिससे कृषि गतिविधियों को नई गति मिली। साथ ही जल उपलब्धता बढ़ने से स्थानीय स्तर पर मत्स्य पालन की शुरुआत हुई, जिसने ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय और रोजगार का नया स्रोत तैयार किया। इस कार्य ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। डबरी में संचित पानी के कारण आसपास के पेड़-पौधों एवं हरियाली के संरक्षण में सहायता मिली। वर्षा के पानी के अनियंत्रित बहाव में कमी आने से मिट्टी कटाव पर भी नियंत्रण हुआ तथा क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन मजबूत हुआ। इससे ग्रामीणों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। डबरी का निर्माण मुक्तिधाम के समीप होने के कारण सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। पहले यहां अंतिम संस्कार जैसी आवश्यक गतिविधियों के दौरान जल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जबकि अब इस डबरी से आवश्यक जल उपलब्ध होने लगा है। इसके साथ ही यह सामुदायिक परिसंपत्ति गांव के अन्य सामाजिक कार्यों में भी उपयोगी साबित हो रही है। आज यह सामुदायिक डबरी ग्राम नवागांव कर्रा के लिए जल संरक्षण और ग्रामीण विकास का एक सफल मॉडल बन चुकी है। इस पहल से जहां एक ओर कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन और भू-जल संरक्षण को मजबूती मिली है, वहीं दूसरी ओर मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। यह कार्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर क्षेत्र के अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणास्रोत है।

27 जुलाई को कलेक्टर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक

बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में 27 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे कलेक्टोरेट के मंथन सभाकक्ष में जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में जल जीवन मिशन से जुड़े सभी कार्यकारी एजेंसियों एवं ठेकेदारों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। पीएचई विभाग के ईई रूपेश धनंजय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार बैठक में मिशन के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसमें सीआईआरपी के तहत निर्धारित समय-सीमा में कार्यों की प्रगति, पूर्ण हो चुकी 219 योजनाओं के भुगतान की स्थिति एवं लंबित प्रकरण, विद्युत, जल स्रोत एवं हर घर जल (॥त्रछ्व) योजनाओं के हस्तांतरण से संबंधित विषयों के साथ तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। सभी कार्यकारी एजेंसियों एवं ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी योजनाओं की अद्यतन प्रगति, आवश्यक अभिलेखों तथा लंबित बिंदुओं की जानकारी के साथ स्वयं अथवा अधिकृत सक्षम प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित रहें।

स्वच्छता व्यवस्थाओं का राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह ने किया निरीक्षण

स्वच्छता नियमों के पालन से बनेगा हर गांव स्वच्छ...

बिलासपुर। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य सलाहकार एवं बिलासपुर संभाग प्रभारी श्रीमती मोनिका सिंह ने आज विकासखंड तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चितावर का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत में संचालित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन का अवलोकन भी किया। स्वच्छग्राही समूह के सदस्यों को नियमित डोर-टू-डोर कलेक्शन, स्रोत पर कचरा पृथक्करण सुनिश्चित कराने तथा स्वच्छता शुल्क के नियमित संग्रह एवं उसके महत्व के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया। राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन तभी सफल होगा, जब प्रत्येक नागरिक स्वच्छता को अपनी दैनिक आदत और सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाएगा। घर से निकलने वाले कचरे का चार प्रकार से पृथक्करण, नियमित डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में सहयोग, स्वच्छता शुल्क का समय पर भुगतान तथा सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने में जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है। ग्राम पंचायत, स्वच्छग्राही एवं ग्रामीण यदि सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, तो प्रत्येक गांव को स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर और कचरा मुक्त बनाया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 का प्रभावी क्रियान्वयन केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निरीक्षण के दौरान स्वच्छग्राहियों एवं ग्रामीणों को कचरे को चार प्रकार से जैसे कि सूखा कचरा, गीला कचरा, सेनेटरी कचरा एवं विशेष देखभाल या इलेक्ट्रॉनिक कचरा को एकत्रित करने की जानकारी दी गई। साथ ही स्वच्छ एवं कचरा मुक्त ग्राम के निर्माण हेतु विस्तार से चर्चा करते हुए स्रोत पर कचरा पृथक्करण एवं वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर ग्राम के सरपंच एवं सचिव को निर्देशित किया गया कि वे ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति निरंतर जागरूक करें, निर्धारित स्थान पर ही कचरे का निस्तारण सुनिश्चित कराएं तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को पहले समझाइश दें एवं आवश्यक होने पर नियमानुसार जुर्माना लगाने की कार्रवाई करें। ग्रामीणों को चार प्रकार से कचरा अलग-अलग रखने, नियमित रूप से स्वच्छता शुल्क का भुगतान करने तथा ग्राम में निर्मित सामुदायिक शौचालय का नियमित उपयोग करने के लिए भी प्रेरित किया गया। निरीक्षण के दौरान जनपद सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर, जिला समन्वयक, जिला सलाहकार, ब्लॉक समन्वयक, बीपीएम (एनआरएलएम), प्रधानमंत्री आवास योजना के तकनीकी सहायक, जनपद पंचायत की टीम, सरपंच, पंचगण, सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बिहान समूह की महिलाएँ, स्वच्छग्राही तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

15 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, BNS व पॉक्सो एक्ट के तहत नरहरपुर पुलिस का एक्शन

अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण के दौरान हुआ था मामले का खुलासा

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/कांकेर:-उत्तर बस्तर कांकेर जिले के नरहरपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के मात्र 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (क्चहस्) तथा पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार 25 जुलाई 2026 को पीड़िता की माता ने थाना नरहरपुर में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को उपचार हेतु शासकीय अस्पताल ले जाया गया था। वहां चिकित्सीय परीक्षण के दौरान बालिका के गर्भवती होने की बात सामने आई। इस पर जब पुलिस द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, तो उसने बताया कि परमेश मंडावी (19 वर्ष) निवासी नरसिंहपुर, थाना कोरर द्वारा उसे बहला-फुसलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना नरहरपुर में अपराध क्रमांक 157/2026 के तहत क्चहस् की धारा 64(1), 64(2)(द्ब), 65(1) एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 व 6 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा

मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तर बस्तर कांकेर निखिल राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (स्ठ्ठक्क) कांकेर मोहसीन खान के पर्यवेक्षण में आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया।

थाना प्रभारी निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर आरोपी के संभावित ठिकाने पर घेराबंदी कर दबिश दी और आरोपी परमेश मंडावी (पिता- बैशाखू मंडावी, उम्र 19 वर्ष, निवासी नरसिंहपुर, थाना कोरर) को हिरासत में लिया। पूछताछ और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।कार्रवाई में इनकी रही मुख्य भूमिका 12 घंटे के भीतर आरोपी को जेल भेजने की इस त्वरित कार्रवाई में नरहरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सोमेश सिंह बघेल, उप निरीक्षक पीयूष कुमार यादव, सहायक उप निरीक्षक (स्ठ्ठ) पलटूराम मंडावी, आरक्षक मनोज ध्रुव, आरक्षक रैन कुमार जैन तथा महिला आरक्षक सरिता गोटी की सराहनीय भूमिका रही।

अग्रवाल सभा दर्री-जमनीपाली की नई कार्यकारिणी घोषित, सुरेश अग्रवाल बने अध्यक्ष

कोरबा। जमनीपाली के साडा कॉलोनी स्थित अग्रसेन भवन में अग्रवाल सभा दर्री जमनीपाली की बैठक सभा के अध्यक्ष प्रेमकुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अग्रवाल सभा दर्री जमनीपाली के आगामी कार्यकाल 2026-2029 के लिए नवीन कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चयन किया गया। सर्वप्रथम अध्यक्ष पद के लिए सुरेश कुमार अग्रवाल (पत्रकार) के नाम का प्रस्ताव प्रेमकुमार अग्रवाल ने रखा जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए बैजनाथ अग्रवाल (भवानी) राजेन्द्र अग्रवाल राजा दर्री, मनीष अग्रवाल दर्री, प्रेमकुमार अग्रवाल सुमेधा का चयन किया गया । मनोज कुमार अग्रवाल एल्डरमेन को एक बार पुनरू सचिव पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। सहसचिव आशीष अ्ग्रवाल बंटी स्याहीमुड़ी को बनाया गया, कोषाध्यक्ष के पद के लिए सुरेश अग्रवाल (बालाजी) के नाम का चयन किया गया । दर्री जमनीपाली अग्रवाल सभा का गठन 2007 में किया गया था तब से आज तक लगातार कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुरेश अग्रवाल बालाजी को दिया जाता रहा है । पहली बार सह कोषाध्यक्ष पद का गठन किया गया, इस पद के लिए अशोक स्टील के संचालक अशोक कुमार अग्रवाल के नाम की घोषणा की गई । मंत्री आशीष अग्रवाल पूर्व एल्डरमेन, प्रचार प्रसार सचिव प्रतीक अग्रवाल और विकास अग्रवाल, श्यामा मेडिकोज को बनाया गया ।

शासकीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल कोनी को मिली अत्याधुनिक ब्लड सेंटर संचालन की अनुमति

मरीजों के लिए अस्पताल में जल्द ही एसडीपी की सुविधा

बिलासपुर। कुमार साहब स्व. श्री दिलीप सिंह जूदेव शासकीय सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल कोनी को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अत्याधुनिक ब्लड सेंटर के संचालन के लिए आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त हो गया है। यह महत्पपूर्ण उपलब्धि जिला प्रशासन, औषधि एवं खाद्य नियंत्रक विभाग के सतत सहयोग एवं मागदर्शन से प्राप्त हुई है। अस्पताल में स्थापित यह अत्याधुनिक ब्लड सेंटर एनटीपीसी सीपत द्वारा सीएसआर मद के अंतर्गत निर्मित किया गया है। आधुनिक उपकरणों और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार यह रक्त केंद्र प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सबसे उन्नत ब्लड सेंटर के रूप में स्थापित हुआ है। इसकी स्थापना एवं विकास में संचालक प्राध्यापक सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. भानु प्रताप सिंह के मार्गदर्शन तथा ब्लड बैंक के क्षेत्र में उनके 25 वर्षों के अनुभव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस ब्लड सेंटर की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यह छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में पहला ऐसा केंद्र बनेगा, जहां सिंगल डोनर प्लेटलेट तैयार करने और मरीजों को उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा डेंगू, कैंसर, बोन मैरो प्रत्यारोपण, थैलेसीमिया और गंभीर रक्त विकारों से पीड़ित मरीजों के उपचार में अत्यंत उपयोगी साबित होगी। इससे मरीजों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाली प्लेटलेट्स उपलब्ध हो सकेंगी और निजी संस्थानों पर उनकी निर्भरता कम होगी। अधीक्षक डॉ. भानु प्रताप सिंह ने बताया कि इस ब्लड सेंटर का उद्देश्य केवल सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण रक्त और रक्त अवयव उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि प्रदेश के मरीजों को विश्वस्तरीय ट्रांसफ्यूजन सेवाएं प्रदान करना भी है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में एसडीपी सुविधा की शुरुआत शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

मलेरिया नियंत्रण और कुपोषण उन्मूलन पर जिला प्रशासन का विशेष फोकस....

■ कलेक्टर ने मलेरिया प्रभावित ग्रामों का किया निरीक्षण

बिलासपुर। जिले में मलेरिया की रोकथाम, समय पर उपचार तथा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज विकासखंड कोटा के मलेरिया प्रभावित ग्राम औरापानी, नवाडीह, मझगांव तथा उप स्वास्थ्य केंद्र मझगांव का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए मलेरिया नियंत्रण, कुपोषण उन्मूलन और नियमित स्वास्थ्य निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ग्राम औरापानी में प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम (पीएफ) मलेरिया के तीन तथा नवाडीह में एक संक्रमित बच्चा चिन्हित हुआ है। सभी बच्चों का प्राथमिक उपचार कर बेहतर चिकित्सा के लिए सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। कलेक्टर ने उप स्वास्थ्य केंद्र मझगांव पहुंचकर भर्ती बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और चिकित्सकों को प्रभावित क्षेत्रों में सघन सर्वे, समय पर जांच तथा गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने ग्राम मझगांव एवं औरापानी के विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा कि यदि कोई बच्चा नियमित रूप से विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र नहीं आ रहा

है तो उसके घर जाकर कारण की जानकारी लें तथा आवश्यकता होने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर उपचार की व्यवस्था कराएं। उन्होंने बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक एवं संतुलित आहार, विशेषकर स्थानीय पोषणयुक्त ष्तिरंगा भोजनष् अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए। आंगनबाड़ी केंद्र मझगांव के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अति कुपोषित बच्चों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने एक अति कुपोषित बच्चे के घर पहुंचकर परिजनों से चर्चा की और बेहतर उपचार एवं पोषण प्रबंधन के लिए बच्चे को पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) रतनपुर ले जाने के लिए प्रेरित किया। परिजनों ने अगले दिन बच्चे को एनआरसी ले जाने की सहमति दी। कलेक्टर ने परिवार को संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं बच्चों की समुचित देखभाल के प्रति जागरूक किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसी भी गांव में मौसमी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना देकर आवश्यक उपचार एवं नियंत्रणात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सभी विभागों को सतत निगरानी एवं समन्वय के साथ कार्य करना होगा।इस अवसर पर एसडीएम कोटा श्री प्रवेश पैकरा, सीएमएचओ डॉ. शुभा गरेवाल, जिला मलेरिया अधिकारी, मलेरिया कंसल्टेंट, खंड चिकित्सा अधिकारी, बीपीएम कोटा, संबंधित सुपरवाइजर, सीएचओ, आरएचओ, मितानिन, ग्राम सरपंच सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

29 जुलाई को कलेक्टर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक

सभी एजेंसियों एवं ठेकेदारों को उपस्थित रहने के निर्देश

बिलासपुर। कलेक्टर एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में 29 जुलाई को सवेरे 10 बजे कलेक्टोरेट के मंथन सभाकक्ष में जल जीवन मिशन अंतर्गत जिले में संचालित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में जल जीवन मिशन से जुड़े सभी कार्यकारी एजेंसियों एवं ठेकेदारों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। पीएचई विभाग के ईई रूपेश धनंजय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार बैठक में मिशन के विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसमें सीआईआरपी के तहत निर्धारित समय-सीमा में कार्यों की प्रगति, पूर्ण हो चुकी 219 योजनाओं के भुगतान की स्थिति एवं लंबित प्रकरण, विद्युत, जल स्रोत एवं हर घर जल (॥त्रछ्व) योजनाओं के हस्तांतरण से संबंधित विषयों के साथ तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। सभी कार्यकारी एजेंसियों एवं ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी योजनाओं की अद्यतन प्रगति, आवश्यक अभिलेखों तथा लंबित बिंदुओं की जानकारी के साथ स्वयं अथवा अधिकृत सक्षम प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से बैठक में उपस्थित रहें।

चार माह 22 दिन बाद 34 मासूमों का अंतिम संस्कार; गमगीन मंजर पर फूट-फूटकर रोया ईरान

तेहरान, एजेंसी। अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के पहले दिन, 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर स्थित शजरे तैय्यबा प्राथमिक विद्यालय पर बमबारी की गई थी। इस हमले में 68 स्कूली बच्चियों के शरीर क्षत-विक्षत अवस्था में मिले थे। इनमें से केवल 34 बच्चों की ही पहचान हो सकी। 22 जुलाई को जब इन मासूमों के ताबूत अंतिम संस्कार के लिए निकाले गए तो पूरा मिनाब शहर गम में डूब गया। हर ओर मातम, आंसू और सन्नाटा पसरा था।

हमले के बाद बचाव दलों को मलबे से बच्चों के शरीरों के केवल टुकड़े ही मिले थे। इनकी पहचान करना बेहद मुश्किल था। महीनों तक चले जटिल डीएनए परीक्षण के बाद करीब चार माह 22 दिन में 34 बच्चों की पहचान संभव हो सकी। इसके बाद ही उनके परिजनों को अंतिम संस्कार की अनुमति दी गई। स्कूल पर हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। कई देशों और मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। जगह-जगह लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए और

निर्दोष बच्चों पर हुए इस हमले को अमानवीय करार दिया।

पहचान पूरी होने के बाद 22 जुलाई को बच्चों के ताबूत राष्ट्रीय झंडे में लपेटकर शहर की सड़कों से अंतिम यात्रा निकाली गई। हजारों लोग नम आंखों से इस यात्रा में शामिल हुए।

इसके बाद मिनाब के शहीदों के कब्रिस्तान में पूरे सम्मान के साथ इन मासूमों को दफनाया गया। 'नो सरेंडर' के नारों से गूंजा ईरान मंगलवार को ईरान के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित तस्वीरों में मिनाब के एक सार्वजनिक चौक पर हजारों लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। पुरुष इस्लामी गणराज्य ईरान के झंडे लहरा रहे थे, जबकि काले चादर (चादोर) ओढ़े महिलाएं अलग समूह में मौजूद थीं। मंच से खुद को मृत बच्ची 'अतेना' की मां बताने वाली एक महिला ने बच्चों की तस्वीरों वाला पोस्टर उठाते हुए उसे 'अमेरिकी अपराधों का दस्तावेज' बताया। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, 'मेरे बच्चे ईश्वर के मार्ग में शहीद हुए हैं।' इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने अमेरिका और इजरायल की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और 'नो सरेंडर' (हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे) के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा।

न्यूयॉर्क में दो लोगों पर चाकू से हमला

एक एशियाई शामिल, पुलिस और ममदानी ने जताई हेट क्राइम की आशंका

न्यूयॉर्क, एजेंसी। न्यूयॉर्क के मैनहैटन के अपर वेस्ट साइड इलाके में दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों पर चाकू से हमला किया गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने राउल मोरालेस को दोनों मामलों में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने कहा कि जांच अधिकारी हमलों के पीछे की वजह की जांच कर रहे हैं। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि क्या यह नफरत फैलाने वाले अपराध का मामला है। न्यूयॉर्क शहर की पुलिस आयुक्त जेसिका एस टिश ने गुरुवार (स्थानीय समय) को जारी बयान में कहा कि दोनों पीड़ितों (एक एशियाई और एक यहूदी व्यक्ति) को माउंट सीनाई सेंट ल्यूक्स अस्पताल ले जाया गया है। दोनों के ठीक होने की उम्मीद है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज दोपहर अपर वेस्ट साइड में दो अलग-अलग हमलों में दो लोगों पर चाकू से हमला किया गया। दोनों पीड़ित को माउंट सीनाई सेंट ल्यूक्स अस्पताल ले जाया गया है और दोनों के बचने की उम्मीद है। पुलिस आयुक्त ने कहा, न्यूयॉर्क पुलिस ने दोनों हमलों के मामले में राउल मोरालेस (51 वर्षीय) को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की तलाश नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी अब भी मामले की जांच कर रहे हैं और हमलों की वजह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। टिश ने कहा कि पीड़ितों और चश्मदीदों के बयानों के अनुसार, मोरालेस ने दोनों हमलों के दौरान 'अल्लाहु अकबर' चिल्लाया था। न्यूयॉर्क पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह नफरत फैलाने वाला अपराध हो सकता है। पुलिस आयुक्त ने यह भी कहा कि विभाग के दस्तावेजों में आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कोई पुराना मामला नहीं है। हालांकि, शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि मानसिक स्वास्थ्य इस घटना का एक कारण हो सकता है। पुलिस ने कहा कि अब तक जांच में आरोपी और दोनों पीड़ितों के बीच या दोनों पीड़ितों के बीच आपसी संबंध का कोई सबूत नहीं मिला है। टिश ने एक आम नागरिक और पुलिसकर्मियों की सराहना भी की। पुलिस को उस जगह तक पहुंचाया, जहां आरोपी छिपा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बिना किसी और के घायल हुए उसे पकड़ लिया।

मेयर ममदानी ने क्या कहा

न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें हमले की जानकारी दे दी गई है और उन्हें राहत है कि दोनों पीड़ितों की हालत स्थिर है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज अपर वेस्ट साइड में हुए इस खौफनाक चाकू के हमले की मुझे जानकारी दी गई है, जिसमें एक एशियाई और एक यहूदी व्यक्ति पर हमला किया गया। पीड़ितों और चश्मदीदों के अनुसार, आरोपी ने दोनों हमलों के दौरान 'अल्लाहु अकबर' चिल्लाया था। मुझे राहत है कि दोनों पीड़ितों की हालत स्थिर है। मेयर ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस ने दोनों हमलों के मामले में राउल मोरालेस को गिरफ्तार कर लिया है।

मारुति सुज़ुकी ने पावर-पैक्ड परफ़ॉरमेंस के साथ New Brezza Turbo Boosterjet लॉन्च की

नई दिल्ली: मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड (मारुति सुज़ुकी) ने युवा भारत के लिए रोमांचक ड्राइविंग परफ़ॉरमेंस देने वाली New Brezza Turbo Boosterjet को लॉन्च करने की घोषणा की है। आज के बहुआयामी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई New Brezza उनके जीवन के हर पहलू में मौजूद विभिन्न व्यक्तित्वों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। New Brezza Turbo Boosterjet ·¤ô Spontaneous Play की सोच के साथ तैयार किया गया है।

यह युवा ट्रेंडसेटर्स के लिए इंजीनियर किया गया है, जो जीवन के हर पहलू में मस्ती और निडरता की तलाश करते हैं। New Brezza टर्बो बूस्टरजेट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,39,900 है। New Brezza, भरोसेमंद और बेहतर K15C डुअल जेट डुअल VVT इंजन और प्रोग्रेसिव स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी उपलब्ध है। 14 लाख से ज़्यादा ग्राहकों के भरोसे को आगे बढ़ाते हुए, New Brezza K15C में नया 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग-माउंटेड पैडल शिफ्टर्स के साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। स्ट्रैटेजिक प्ले की अपनी पहचान के साथ New Brezza K15C अपने सेगमेंट में दबदबा बनाए रखती है और उन महत्वाकांक्षी प्रोफेशनल्स को आकर्षित करती है, जिनकी पसंद उनके लक्ष्यों और सपनों से जुड़ी होती है।

New Brezza के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, मारुति सुज़ुकी इंडिया लिमिटेड के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ़िसर, मार्केटिंग एंड सेल्स, श्री पार्थो बनर्जी ने कहा, "New Brezza एक ऐसी एसयूवी है जो वास्तव में युवा भारत की आकांक्षाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। New Brezza Turbo Boosterjet के साथ हम ड्राइविंग के रोमांच का एक नया आयाम जोड़ रहे हैं जो युवा भारत की ऊर्जा और वाइब से पूरी तरह मेल खाता है। New Brezza को ग्राहकों की अलग-अलग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, क्योंकि यह उनके विभिन्न मूड और अवसरों के अनुकूल आसानी से ढल जाती है। यह एक ऐसी एसयूवी है जो ग्राहक की पर्सनालिटी के हर पहलू के साथ सामंजस्य स्थापित करती है, चाहे वह काम पर हों या खेल-कूद के मूड में— उनकी जीवनशैली के विविध पहलुओं से मेल खाती है और उन्हें लीड एवरी प्ले ('Lead Every Play') में सक्षम बनाती है। यही एक बेहतरीन प्रोडक्ट की असली पहचान है, जो ग्राहकों के अनुसार ढल जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि New Brezza भारत की पसंदीदा कॉम्पैक्ट एसयूवी के रूप में इस ब्रांड की विरासत को और आगे बढ़ाएगी।

दूसरों की किस्मत बताने वाली खुद नहीं जान पाई अपना भविष्य! मॉस्को में पावर बैंक फटने से झुलसीं इन्फ्लुएंसर अन्ना

मॉस्को, एजेंसी। रूस की महिला इन्फ्लुएंसर और ज्योतिष अन्ना ओटाविना के मॉस्को स्थित पेंटहाउस में रात के समय बिस्तर पर रखा पावर बैंक फठ गया। पावर बैंक ओवरहीट होकर ब्लास्ट हुआ, इससे अन्ना ओटाविना की पीठ का 30 फीसदी हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया और बाल भी जल गए।

इस घटना के बाद अन्ना ने अपने फॉलोअर्स को सतर्क करते हुए चेतावनी दी है कि सोते समय या बिस्तर जैसी नरम सतहों पर पावर बैंक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्जिंग पर छोड़ना जानलेवा साबित हो सकता है।

वहीं इस घटना के बात इस बात की भी चर्चा हो रही है कि दूसरों की किस्मत बताने वाली ज्योतिष खुद का भविष्य नहीं जान पाई, जिसके कारण इस दुर्घटना का शिकार होना पड़ा।

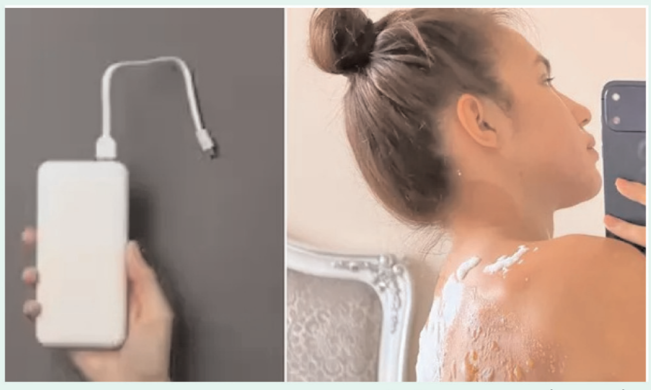

कैसे लगी आग? अन्ना ओटाविना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में बताया कि उनका पोर्टेबल चार्जर, जिसे उन्होंने फोन चार्ज करने के लिए बिस्तर पर रखा था, अचानक बहुत ज्यादा गर्म हो गया। जिसके कारण ब्लास्ट हो गया और वो घायल हो गई।

ओटाविना का कहना है पावर बैंक इसलिए ब्लास्ट हुआ, क्योंकि वह इसे किसी ठोस, हवादार सतह के बजाय नरम बिस्तर पर रख दी थी, जिसके कारण वह बहुत गर्म हो गया।

वह पावर बैंक की ओर पीठ करके सो रही थी, जिसके कारण पीठ का लगभग 30 फीसदी हिस्सा जल गया और बाल भी झुलस गए।

जैसे ही वह उछली, आग की लपटें उनके बालों तक पहुंच चुकी थीं। जलते हुए बाल उसकी पीठ पर गिरे और उसकी त्वचा को झुलसा दिया, इससे पहले कि उन्हें समझ आता कि क्या हो रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि स्थिति एक छोटी सी चिंगारी से कहीं अधिक गंभीर थी। उनके तकिया और कंबल जल रहे थे, और पावर बैंक जमीन पर गिर गया था।

ओटाविना ने बताया कि उन्होंने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए आग पर खुद काबू पाने की कोशिश की। उन्होंने जलते हुए पावर बैंक को ढककर लपटों को बुझाया और फिर अपने बिस्तर और कालीन पर लगी आग को भी बुझाया। इसके बाद वह उपचार के लिए डॉक्टर के पास गईं। जहां उनके पीठ के लगभग 30 फीसदी हिस्से जलने की पुष्टि हुई।

निगम जोन 7 ने वार्ड 22 में शनिवार को 35 सफाई कामगारों के गैंग से चलाया विशेष सफाई अभियान

रायपुर। आज शनिवार को रायपुर नगर निगम जोन 7 स्वास्थ्य विभाग द्वारा जोन अंतर्गत डॉ ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 22 के क्षेत्र में 35 सफाई कामगारों के विशेष गैंग से सफाई अभियान चलाया गया. इसमें जोन के प्रत्येक वार्ड के 5 सफाई कामगारों ने वार्ड 22 क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया. प्रत्येक शनिवार को एक वार्ड की सफाई नगर निगम जोन 7 स्वास्थ्य विभाग द्वारा 35 सफाई कामगारों के विशेष गैंग से करवाई जाएगी. आज डॉ ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड क्रमांक 22 में 35 सफाई कामगारों के गैंग द्वारा की गयी विशेष सफाई के अभियान का वार्ड में प्रत्यक्ष निरीक्षण वार्ड 22 की पार्षद मीना ठाकुर द्वारा एमआईसी सदस्य भोलाराम साहू एवं जोन 7 जोन कमिश्नर डॉ तृप्ति पाणीग्रही सहित अन्य सम्बंधित जोन अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया.

भारत ने यूएन में लगाई पाकिस्तान को लताड़

पीओके में कश्मीरियों के दमन की गवाह है पूरी दुनिया

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ा जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भ्रामक प्रचार करने के बजाय अपने देश और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में हो रहे दमन पर ध्यान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में 'विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तंत्र को मजबूत करने' विषय पर आयोजित खुली बहस में भारत का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हालिया घटनाक्रम पाकिस्तान की वास्तविकता को उजागर करते हैं।'

भारत ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया: राजदूत पी. हरीश ने आगे कहा, 'पूरी दुनिया पीओके में कश्मीरियों के बुनियादी अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी के लगातार दमन की गवाह है। यह कोई अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि करीब आठ दशकों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपनाई जा रही एक व्यापक नीति का हिस्सा हैं। यही स्थिति पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है।' उन्होंने पाकिस्तान की आंतरिक राजनीतिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लोकतांत्रिक

संस्थाएं लगातार कमजोर हुई हैं। उन्होंने कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं की गिरफ्तारी, मुख्य विपक्षी दल को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना, 27वें संविधान संशोधन के जरिए सेना का संवैधानिक हस्तक्षेप और ऐसे अन्य कदमों ने लोकतंत्र की बची-खुची व्यवस्था को भी कमजोर कर दिया है।' 'जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा : स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर मुद्दा उठाने को वैश्विक मंच का दुरुपयोग बताया। उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और रहेगा। यह भारत की संवैधानिक और कानूनी वास्तविकता है, जिसे पाकिस्तान जानबूझकर नजरअंदाज करता है।' उन्होंने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के संबंध में एकमात्र लंबित मुद्दा भारत के संप्रभु क्षेत्र पर पाकिस्तान का खुला आक्रमण और उसका अवैध कब्जा है।'

भ्रामक प्रचार बंद करे पाकिस्तान: पी. हरीश

भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, 'पाकिस्तान को चाहिए कि वह धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर झूठा प्रचार करने और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को गुमराह करने के बजाय अपने देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दे।' भारत ने यह भी कहा कि अन्य देशों में इस तरह की घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र तीखी प्रतिक्रिया देता है, लेकिन पाकिस्तान में हो रहे ऐसे दमन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना दिया जाना चाहिए।

अमेरिका ने फिर फोड़ा टैरिफ बम

भारत समेत 17 देशों पर लगाया 10 फीसदी शुल्क, क्या पाकिस्तान का नाम भी है शामिल

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर कार्रवाई करते हुए भारत सहित 17 देशों से आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जैमीसन ग्रीर ने शुक्रवार को 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत 60 देशों पर नए शुल्क की घोषणा की। यह फैसला सभी देशों पर लगाए गए अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क की अवधि समाप्त होने से एक दिन पहले लिया गया।

यूएसटीआर के बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर जैमीसन ग्रीर ने उन 60 अर्थव्यवस्थाओं पर अंतिम कार्रवाई की है, जिन्होंने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर प्रभावी रोक लगाने और उसे लागू करने में विफलता दिखाई है। ग्रीर ने कहा, 'यह कदम मानवाधिकारों के उल्लंघन और व्यापार में पैदा हुई विकृतियों को दूर करने की दिशा में है, ताकि दुनिया भर के श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके।' 10 प्रतिशत

शुल्क भारत, कनाडा, ब्रिटेन, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत 17 देशों पर लागू होगा। इससे पहले प्रस्तावित सूची में भारत को 12.5 प्रतिशत शुल्क वाले देशों की श्रेणी में रखा गया था। इस संबंध में जारी संघीय नोट में कहा गया कि जून में प्रस्तावित शुल्क की घोषणा के बाद भारत ने जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया। 14 जून को भारत ने अपनी विदेश व्यापार नीति में संशोधन कर जबरन श्रम से तैयार वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप प्रशासन ने ये दोनों जांच उस समय शुरू की थीं, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में पिछले वर्ष लगाए गए 'पारस्परिक शुल्क (रिसिप्रोकल टैरिफ)' को आपातकालीन शक्तियों के तहत अवैध करार दिया था। इसके बाद प्रशासन ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाया था, जिसकी अवधि शुक्रवार को समाप्त हो रही है। भारत ने यूएसटीआर की दोनों जांचों पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता के दौरान चर्चा की जा सकती है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 141 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

होर्मुज पर जंग तेज: अमेरिका का ईरान पर लगातार 13वीं रात हमला, तेल 100 डॉलर के पार

वाशिंगटन, एजेंसी। होर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने गुरुवार को ईरान पर लगातार 13वीं रात हमले किए। वहीं, यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। इन घटनाओं ने पूरे पश्चिम एशिया में संघर्ष के और फैलने की आशंका बढ़ा दी है। इसका असर वैश्विक बाजार पर भी दिखा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई।

आखिर अमेरिका ने नए हमले क्यों किए: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ताजा हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है, जिसके जरिए वह क्षेत्रीय जलक्षेत्र से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों और आम नाविकों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य में अंतरराष्ट्रीय नौवहन को सुरक्षित और सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान में कहां-कहां हुए धमाके अमेरिकी हमलों के कुछ ही समय बाद ईरान के सरकारी मीडिया ने बंदर अब्बास और केशम द्वीप के पास, जो

होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट स्थित हैं, धमाकों की जानकारी दी। इसके अलावा उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों एंडिमेश्क और ओमिदियेह के आसपास भी विस्फोटों की खबर सामने आई। हालांकि, इन धमाकों से हुए नुकसान की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

हूती विद्रोहियों की नई चेतावनी कितनी गंभीर है: इस बीच हूती विद्रोहियों ने एक और महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग को बाधित करने की धमकी दी है। पहले ही ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य बंद किए जाने से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो चुकी है। सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और गैस की आपूर्ति इसी समुद्री मार्ग से होती है। ऐसे में कई देश अब वैकल्पिक शिपिंग रूट तलाशने में जुट गए हैं।

ट्रंप ने ईरान और हूतियों को क्या चेतावनी दी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि यदि जहाजों पर हमले जारी रहे तो हूती विद्रोहियों को 'कड़ी सैन्य सजा' दी जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यदि भविष्य में ऐसे हमले दोबारा हुए तो अमेरिका इसके लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार मानेगा, क्योंकि हूती संगठन ईरान के समर्थन से काम करता है। ट्रंप ने कहा कि ईरान और हूतियों–दोनों को इसका गंभीर सैन्य परिणाम भुगतना पड़ेगा।

तेल बाजार पर कितना पड़ा असर: लगातार बढ़ते तनाव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत गुरुवार को छह प्रतिशत से अधिक उछलकर लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। यह मई में हुए अस्थायी शांति समझौते के बाद का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समुद्री मार्ग लंबे समय तक बाधित रहा तो वैश्विक महंगाई और ऊर्जा संकट और गहरा सकता है।

क्या कूटनीति से टल सकता है बड़ा युद्ध: इराक के प्रधानमंत्री अली अल-जैदी, जिनके अमेरिका और ईरान दोनों से करीबी संबंध हैं, गुरुवार को तेहरान पहुंचे और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। उनके कार्यालय ने कहा कि इराक अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी सैन्य हमले के लिए नहीं होने देगा। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद में चेतावनी देते हुए कहा कि पूरा क्षेत्र तेजी से व्यापक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट का एकमात्र समाधान कूटनीति और संवाद है तथा पाकिस्तान समेत सभी मध्यस्थ देशों के प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए।

मशरूम उत्पादन से बदली जिंदगी : बिहान ने पुष्पा साव को बनाया आत्मनिर्भर

हौसले और बिहान के सहयोग से लिखी सफलता की नई इबारत

मजदूरी से स्वरोजगार तक का प्रेरक सफर, मशरूम उत्पादन से सालाना डेढ़ लाख रुपये की आयए कुरमापाली की पुष्पा साव ने मेहनत

रायगढ़/मूक पत्रिका

कभी मजदूरी ही परिवार की आजीविका का एकमात्र सहारा थी। दिनभर की कड़ी मेहनत के बाद भी आय इतनी नहीं होती थी कि घर की सभी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें। बच्चों की पढ़ाई, परिवार का भरण-पोषण और भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती थी। लेकिन आज वही पुष्पा साव मशरूम उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ने के बाद उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति बदली, बल्कि अपने आत्मविश्वास और सम्मान को भी नई पहचान दिलाई। आज वे मशरूम उत्पादन से सालाना लगभग 1.50 लाख रुपए की आय अर्जित कर रही हैं और अपने गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं।

आर्थिक तंगी से जूझ रहा था परिवार, बिहान से मिली नई दिशा-रायगढ़ जिले के ग्राम कुरमापाली निवासी श्रीमती पुष्पा साव बताती हैं कि कुछ वर्ष पहले तक उनका परिवार पूरी तरह मजदूरी पर निर्भर था। मेहनत के बावजूद आमदनी सीमित थी, जिससे परिवार का खर्च चलाना भी कठिन हो जाता था। बच्चों की अच्छी शिक्षा और परिवार के बेहतर भविष्य का सपना आर्थिक अभाव के कारण अधूरा लगता था। ग्राम पंचायत के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की जानकारी मिली। उन्होंने संस्कार स्व-सहायता समूह से जुड़कर नियमित बचत शुरू की। समूह के माध्यम से प्रशिक्षण, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड (सीआईएफ) तथा बैंक से वित्तीय सहयोग प्राप्त हुआ। यही सहयोग उनके जीवन में बदलाव का आधार बना।

आर्थिक मजबूती के साथ बढ़ा आत्मविश्वास-पुष्पा साव ने सीआईएफसे प्राप्त 10 हजार रुपए की राशि से घर पर मशरूम उत्पादन शुरू किया। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और लगातार मेहनत से उनके मशरूम की स्थानीय बाजार में अच्छी मांग बनने लगी। बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने लगभग 70 हजार का अतिरिक्त निवेश कर अपने व्यवसाय का विस्तार किया। आज वे मशरूम उत्पादन से सालाना लगभग 1.50 लाख रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है। मशरूम उत्पादन से होने वाली आय ने पुष्पा साव के परिवार को आर्थिक संबल दिया है। अब वे बच्चों की बेहतर शिक्षा, घरेलू जरूरतों और भविष्य की बचत पर ध्यान दे पा रही हैं। परिवार के भोजन में भी मशरूम शामिल होने से पोषण स्तर में सुधार आया है।

दूसरी महिलाओं के लिए बनीं प्रेरणा-पुष्पा साव कहती हैं कि यदि उन्हें बिहान का सहयोग नहीं मिला होता, तो शायद आज भी उनका परिवार मजदूरी पर ही निर्भर रहता। आज वे सम्मानपूर्वक अपना व्यवसाय संचालित कर रही हैं और गांव की अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सही मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ और निरंतर मेहनत किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान हम ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में नए अवसर प्रदान कर रहा है।

ह्श्श्ञ आंदोलन में युवाओं की आवाज़ हुई बुलंद, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस का विजय जुलूस

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुरः-जिला कांग्रेस कमेटी कांकेर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर/ग्रामीण, युवा कांग्रेस एवं एनएसयूआई के संयुक्त तत्वावधान में आज पुराना बस स्टैंड से अंबेडकर चौक तक छात्रों के सम्मान में भव्य विजय मार्च एवं आतिशबाजी का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, छात्र-छात्राएं एवं आम नागरिक शामिल हुए।

विजय मार्च का आयोजन देशभर के छात्रों द्वारा निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर चलाए गए आंदोलन के समर्थन में किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों के लगातार संघर्ष और देशव्यापी जनदबाव के परिणामस्वरूप केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को सफलता मिली, जिसे छात्रों की लोकतांत्रिक लड़ाई और जनशक्ति की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि यह जीत उन लाखों युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित है जिन्होंने अपने भविष्य की रक्षा के लिए आवाज़ बुलंद की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बसंत यादव के नेतृत्व में निकले इस विजय मार्च में पूरे मार्ग पर नारेबाजी और आतिशबाजी कर छात्रों के संघर्ष का सम्मान किया गया।

इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसंत यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज़ को संसद से लेकर सड़क तक पूरी मजबूती के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए प्रधानमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनके साथ किया गया व्यवहार लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें चोट भी आई। यह लोकतंत्र और विपक्ष की गरिमा के लिए चिंताजनक है। बसंत यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा असहमति की आवाज़ को दबाने के बजाय उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस आगे भी संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस नेता विजय ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा छात्रों, युवाओं और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। लोकतंत्र की रक्षा तथा युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पार्टी सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी। कार्यक्रम में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सुमित राय तथा युवा कांग्रेस के शेष गजबिए, यशपाल कांगे एवं जीशान अली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरे विजय मार्च के दौरान युवाओं ने नारेबाजी करते हुए छात्रों के सम्मान और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को बुलंद किया।

कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसंत यादव, प्रदेश महामंत्री नरेश ठाकुर, विजय ठाकुर, जिला महामंत्री उदय प्रकाश शर्मा (बंटी), ठाकुर राम कश्यप, नीरा साहू, मृदुला भास्कर, ब्लॉक अध्यक्ष यासीन करानी, लोमेंद्र यादव, भारती सलाम, मनोज जैन, अजय भास्वानी, गफ्फार मेमन,पंच राम सलाम ,

पवन कांगे, निरंजन भास्कर, लतीफ मेमन ,संग्राम नेताम, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष, अजय सिंह रेनू, मुकेश तिवारी, बबलू देवांगन, विजय यादव, अधिवक्ता के. डी. मिश्रा, झमिट कड़ियाम, जयप्रकाश गावड़े,चंद्रलोक, जितेंद्र वैध, इसहाक अहमद, टुकेश्वर साहू, सतीश दीपक, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सुमित राय, शेष गजबिए, यशपाल कांगे, अर्जुन देवांगन, युवा शहर कांग्रेस अध्यक्ष जीशान अली, भौम सिंह नाग, सोमेश सोनी, अमन गायकवाड़, प्रतीक मेश्राम, रोशन आरा, लता मांडवी, साधना सलाम, चंद्र प्रभा, विद्या सिन्हा, रंजन गोस्वामी, प्रशांत सिन्हा, अमित साहू, आलोक श्रीवास्तव, आयुषी मिश्रा, यास्मीन खान, सुमति, ईश्वर सोनवानी, प्रशांत तिवारी, आयुष तिवारी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक एवं आम नागरिक उपस्थित रहे।

नारी सम्मान निधि योजना के नाम पर करोड़ों की ठगीः दूसरा आरोपी गिरफ्तार, सैकड़ों महिलाओं को रकम दोगुनी करने का दिया था लालच..,

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

नारी सम्मान निधि योजना के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से करोड़ों रुपये की कथित ठगी के मामले में सारंगढ़ पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। मामले में दूसरे आरोपी अजय लक्ष्मै को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का आरोप है कि आरोपियों ने महिलाओं को 20 माह में रकम दोगुनी करने और जमा राशि पर हर माह 10 प्रतिशत अनुदान मिलने का झांसा देकर बड़ी रकम जमा कराई थी। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमीषा पाण्डेय के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय लक्ष्मै निवासी ग्राम छर्रा, थाना सारंगढ़ को गिरफ्तार किया। इससे पहले इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, जेवरा सहित आसपास के गांवों की महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अजय लक्ष्मै, दिनेश बंजारे, उत्तम बाई बंजारे और अन्य एजेंट गांव-गांव जाकर स्वयं को ÷छत्तीसगढ़ युवा समाज सुधार समिति÷ का सदस्य बताते थे। वे दावा करते थे कि उनकी ÷नारी सम्मान निधि योजना÷ सरकारी योजना है, जिसमें पैसा जमा करने पर 20 माह में राशि दोगुनी हो जाएगी। साथ ही हर माह जमा राशि पर 10 प्रतिशत अनुदान और बैंक से ऋण लेकर पैसा जमा करने पर उसकी किश्त संस्था द्वारा भरने का भी लालच दिया जाता था। इसी झांसे में आकर सैकड़ों महिलाओं और अन्य लोगों ने संस्था में रकम जमा कर दी। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने करीब 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार 260 रुपये की ठगी की है। जांच के बाद थाना सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी अजय लक्ष्मै ने मामले में अपनी भूमिका स्वीकार की। पुलिस ने उसके कब्जे से एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और लेनदेन से जुड़े रजिस्टर जब्त किए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।इस कार्रवाई में कोतवाली प्रभारी प्रमोद यादव, सउनि नरेंद्र मनहर, प्रधान आरक्षक भँवर काटले, आरक्षक मिनिकेतन पटेल, आरक्षक अरविंद सिदार, आरक्षक योगेश एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही ठगी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और लेनदेन की भी जांच की जा रही है।

बकावंड की समाजसेवी द्रोपती देवांगन बनीं सीताराम मानस मंडली की अध्यक्ष, क्षेत्र में हर्ष का माहौल

बकावंड/मूक पत्रिका

क्षेत्र की सक्रिय समाजसेवी एवं वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता श्रीमती द्रोपती देवांगन को सीताराम मानस मंडली, बकावंड का अध्यक्ष चुना गया है। उनके चयन से क्षेत्र के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों में खुशी और उत्साह का माहौल है। समाज के विभिन्न वर्गों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में मानस मंडली धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगी।श्रीमती द्रोपती देवांगन लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं। उन्होंने भाजपा के मंडल एवं जिला स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए संगठन को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। संगठनात्मक कार्यों के साथ-साथ वे सामाजिक सेवा, महिला सशक्तिकरण तथा धार्मिक आयोजनों में भी सक्रिय रूप से योगदान देती रही हैं।क्षेत्रवासियों का कहना है कि द्रोपती देवांगन का सरल व्यक्तित्व, संगठन क्षमता और समाज के प्रति समर्पण उन्हें एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनाता है। यही विश्वास उन्हें सीताराम मानस मंडली जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक संगठन की जिम्मेदारी मिलने का आधार बना है।अपने चयन पर श्रीमती द्रोपती देवांगन ने मंडली के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को साथ लेकर भगवान श्रीराम के आदर्शों के अनुरूप धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि मानस मंडली के माध्यम से समाज में संस्कार, सद्भाव, सामाजिक समरसता और एकता का संदेश और अधिक मजबूत किया जाएगा।उनकी नियुक्ति को क्षेत्र में धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समाज के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनके नेतृत्व में सीताराम मानस मंडली नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी।

कांकेर में मलेरिया का तांडवः दो नौ वर्षीय स्कूली बच्चों की मौत से हड़कंप, 11 से अधिक छात्र संक्रमित

डोमाहरा और मर्दापोटी के दो बच्चों ने तोड़ा दम, हॉस्टलों में अचानक आउटब्रेक से अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन कांकेर।

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुरः कांकेर जिले में मलेरिया का प्रकोप तेजी से पांव पसार रहा है। बीते दो दिनों के भीतर मलेरिया की चपेट में आने से दो नौ वर्षीय स्कूली बच्चों की असामयिक मौत हो गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और हड़कंप का माहौल है। वहीं दूसरी ओर, इरादाह और मर्दापोटी छात्रावासों में रहने वाले 11 से अधिक छात्र मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार सामने आ रहे मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, डोमाहरा निवासी तीन सगी बहनों को तेज बुखार की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार के दौरान 9 वर्षीय करीना विश्वकर्मा की 25 जुलाई को मौत हो गई, जबकि उसकी दो अन्य बहनों का अस्पताल में इलाज जारी है। दूसरी घटना मर्दापोटी छात्रावास की है, जहां सिर दर्द और तेज बुखार की शिकायत पर छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई। शुरुआत में चार छात्र मलेरिया पॉजिटिव मिले। इनमें से 9 वर्षीय छात्र सुभाष कुमेटी की स्थिति बिगड़ने पर परिजन उसे अपने साथ ले गए थे। रविवार सुबह तबीयत अत्यधिक खराब होने पर उसे पुनः जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

हॉस्टलों और प्रभावित गांवों में लगे स्वास्थ्य शिविर-मामला उजागर होते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने प्रभावित छात्रावासों और गांवों में डेरा डाल दिया है। इरादाह और मर्दापोटी में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर बच्चों की जांच, रक्त नमूने लेने, दवा वितरण एवं त्वरित उपचार की व्यवस्था की जा रही है। विभाग द्वारा जिले के सभी छात्रावासों में विशेष निगरानी और लगातार स्वास्थ्य परीक्षण के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।

22 जुलाई तक नहीं था कोई मामला, अचानक बढ़ा संक्रमणः अधिकारी-मामले पर जानकारी देते हुए आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त जया मन्नू ने बताया कि 22 जुलाई को सभी छात्रावासों में बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया था, उस समय कोई भी बच्चा मलेरिया से संक्रमित नहीं पाया गया था। 24 जुलाई के बाद अचानक मामले सामने आने शुरू हुए हैं। वहीं, कांकेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (ष्टरूह्र) डॉ. आर. सी. ठाकुर ने कहा, ÷जिले में अचानक मलेरिया का आउटब्रेक देखा जा रहा है। हमारी स्वास्थ्य टीमें लगातार हॉस्टलों और संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर परीक्षण कर रही हैं। 22 तारीख तक जिन बच्चों की जांच हुई थी वे नेगेटिव थे, लेकिन 24 तारीख के बाद अचानक मामले बढ़े और दो मासूमों की जान चली गई। वर्तमान में इरादाह और मर्दापोटी सहित सभी छात्रावासों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर सतर्कता बरती जा रही है।÷

रोकथाम व नियंत्रण पर प्रशासन की नजर अचानक फैले इस प्रकोप के बाद अब प्रशासन की प्राथमिक प्राथमिकता संक्रमण की रोकथाम और मरीजों को त्वरित इलाज उपलब्ध कराना है। देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस बढ़ते प्रकोप पर कितनी जल्द पूरी तरह से काबू पाता है।

ग्राम पंचायत एकताल के जनप्रतिनिधियों ने उठाए सवाल, पोर्टल में 'निराकृत' तो हकीकत में अधूरे हैं कार्य

सुशासन तिहार की शिकायतें कागजों में निराकृत, जमीनी स्तर पर समाधान का इंतजार

रायगढ़/मूक पत्रिका

प्रदेश शासन द्वारा आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित सुशासन तिहार के दौरान ग्राम पंचायत एकताल में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े मामलों को लेकर कई शिकायतें और मांगें दर्ज कराई थीं। लेकिन शिविर आयोजित होने के कई महीने बाद भी अधिकांश मामलों का जमीनी स्तर पर समाधान नहीं हो सका है। इसके विपरीत ऑनलाइन पोर्टल में कई शिकायतों और मांगों की स्थिति ÷निराकृत÷ दर्शाई जा रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों में नाराजगी और आश्चर्य का माहौल है।गौरतलब हो कि आयोजित सुशासन तिहार के शिविर में ग्राम एकताल के सरपंच द्वार अवैध कब्जे की शिकायत, टॉवर लगाने की मांग, सीसी रोड निर्माण, खेल मैदान का विकास, पंचायत क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्य तथा राज्यसभा सांसद मद से स्वीकृत कार्य प्रारंभ नहीं होने जैसी शिकायतें एवं मांगें दर्ज कराई गई थीं। इनमें से कई आवेदन आज भी लंबित हैं, जबकि कुछ मामलों को ऑनलाइन पोर्टल पर ÷निराकृत÷ बताया जा रहा है। पोर्टल की सूची के अनुसार कुछ आवेदनों की स्थिति ÷निराकृत÷ दर्ज है। इनमें ग्राम पंचायत एकताल में खेल मैदान के विकास, सीसी रोड निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों से संबंधित मांगें शामिल हैं। जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का दावा है कि इन कार्यों का धरातल पर कोई समाधान नहीं हुआ और न ही उन्हें किसी प्रकार की कार्रवाई की जानकारी दी गई।जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि किसी शिकायत या मांग का वास्तव में निराकरण हुआ है, तो इसकी जानकारी संबंधित आवेदक अथवा पंचायत प्रतिनिधियों को भी मिलनी चाहिए। लेकिन उन्हें ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में बिना वास्तविक कार्रवाई के पोर्टल पर मामलों को ÷निराकृत÷ दर्शाना कई सवाल खड़े करता है।

शासन की मंशा पर गैर रहे पानी

ग्रामीणों का आरोप है कि यदि केवल आंकड़ों में शिकायतों का निपटारा दिखाया जाएगा और जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी, तो सुशासन तिहार जैसे जनहितकारी अभियान की मंशा पर भी प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।जनप्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि शासन का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है, लेकिन यदि अधिकारी केवल पोर्टल पर प्रकरणों का निस्तारण दर्ज कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लें, तो इससे शासन की मंशा प्रभावित होती है।

क्या कहते है हिमांशु चौहान

सरपंचग्राम पंचायत एकताल =सुशासन तिहार में दिए गए आवेदनों को ऑन लाईन पोर्टल में निराकृत दिखाया जा रहा है।जबकि कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया।जो कि शासन की मंशा पर अधिकारियों की लापरवाही को साबित कर रहा है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।